सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 23, नई दिल्ली । शुक्रवार, 05 अप्रैल 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है।

03 भगत सिंह और अंबेडकर के बीच क्यों लगी थी CM केजरीवाल की तस्वीर?
06 प्रदेश में भी बने भारत मंडपम
08 मेरठ से' राम को हराने' पर तुले हैं अखिलेश,तीसरी बार बदला कैंडीडेट

दिल्ली परिवहन विभाग का सामने आया बड़ा और नया झोल, कैसे आला अधिकारी ने अपनी इच्छा से बनवा रखी है आनलाइन एप्लीकेशन

संजय बाटला

नई दिल्ली। आपकी जानकारी के लिए फिर से आपकों याद करवा दें दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल वाहनो को परमिट लेना अनिवार्य है उसमे से कई परमिट परिवहन विभाग भी केबिनेट से आज्ञा लिए बिना जारी नही कर सकता और केबिनेट की आज्ञा के बाद भी ड्रा द्वारा जारी किया जाता हैं और साथ ही दिल्ली में आटो तीन पहिया पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 100000 (एक लाख) पर बंदिश लगा रखी है। ऐसे वाहनों जिन के लिए बंदिश/सीमा बंदिश होती है उसके लिए मोटर वाहन नियम में रिप्लेसमेंट मोड़ में परमिट डिपोजिट आनलाइन आवेदन प्रक्रिया में उपल्ब्ध है पर दिल्ली के परिवहन विभाग के आला अधिकारियों ने आनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अपनी इच्छानुसार बंदिश परमिटो के लिए अलग अलग कागजों की जरूरत डलवा रखी है। आटो के अलावा अन्य सभी बंदिश परमिटो पर परिवहन विभाग द्वारा अंदाजन 7 से 10 कागज अपलोड करने के बाद रिप्लेसमेंट डिपोजिट स्लिप कि फीस कटती है पर आटो की रिप्लेसमेंट डिपोजिट स्लिप के लिए परिवहन विभाग ने सिर्फ दो कागज अपलोड करना अनिवार्य करवा रखा है जिसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में परमिट को रिप्लेसमेंट मोड में जमा करवाने के लिए वाहन मालिक द्वारा कमा करने की किसी भी आधार पर जरुरत नहीं है पर और उन दो कागजों को आटो शाखा से प्राप्ति करने की लिए आटो तीन पहिया वाहन मालिक को आटो शाखा में कम से कम तीन बार जाना पड़ता हैं जब की इन दोनो कागजों में से किसी एक की भी आवश्यकता ही नहीं क्योंकि वह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में ही उपल्ब्ध है और दूसरा महत्वपूर्ण कागज परमिट रिप्लेसमेंट डिपोजिट स्लिप जारी होने के बाद नए वाहन के पंजीकरण के समय जरूरी है ना की परमिट डिपोजिट के समय। आटो के लिए परमिट को रिप्लेसमेंट आनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अपनी इच्छा के पेपर अपलोड करवाने के बाद भी हस्तचालित कार्यशैली से काम करवाने की आज्ञा देना और सिर्फ आटो के लिए ऐसे कागजों को अनिवार्य करवाना जो ऑनलाइन ही उपल्ब्ध है वाहन पोर्टल पर?

अब आप समझ सकते है की क्यों दिल्ली में आटो माफिया फल फूल रहा है और कोन उन्हे फलने फूलने में अंदर से दे रहा है साथ।

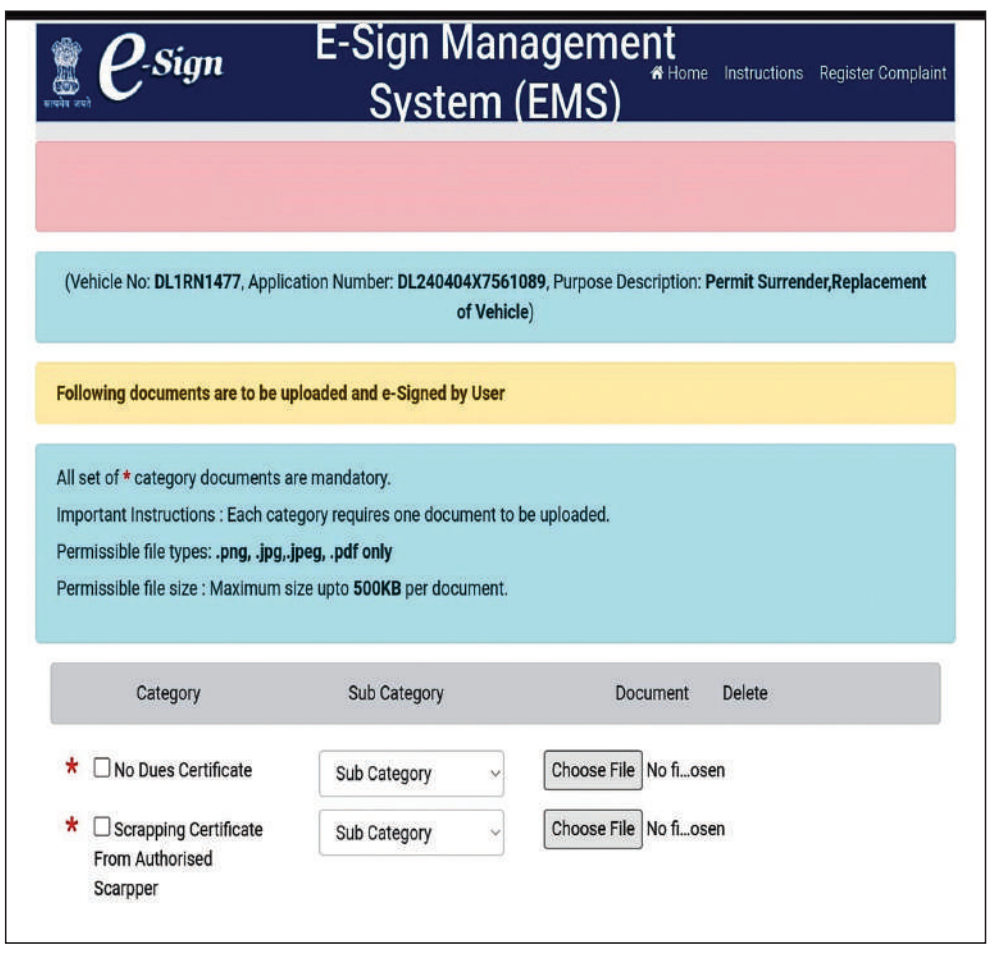

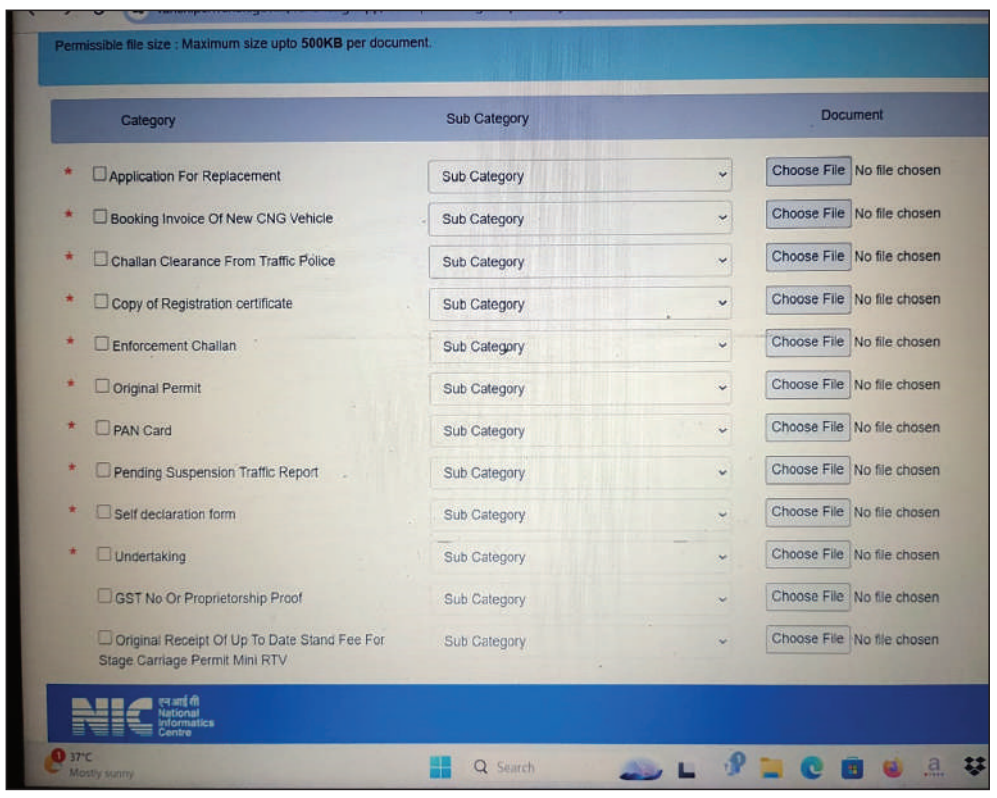

कल के समाचार पत्र में विशेष : टोलवा दिल्ली परिवहन विभाग में कार्यरत पिछले 5 वर्षों से आज तक के आला अधिकारियों के द्वारा जारी आदेशों/कार्यों की निष्पक्ष जांच की करेगा मांग और साथ ही ईडी, सीबीआई से भी करेगा मांग जाने आखिर क्यों और क्या है कारण और कोन से आदेश है जिसे जनता की जगह मिला किसी और को फायदा।

विशेष परिवहन आयुक्त स्क्रैप पालिसी एस.ओ.पी. जारी होने के बाद भी नही जारी करना चाहते निर्धारित समय सीमा समाप्त व्यवसायिक वाहनों को एनओसी आखिर क्यों?

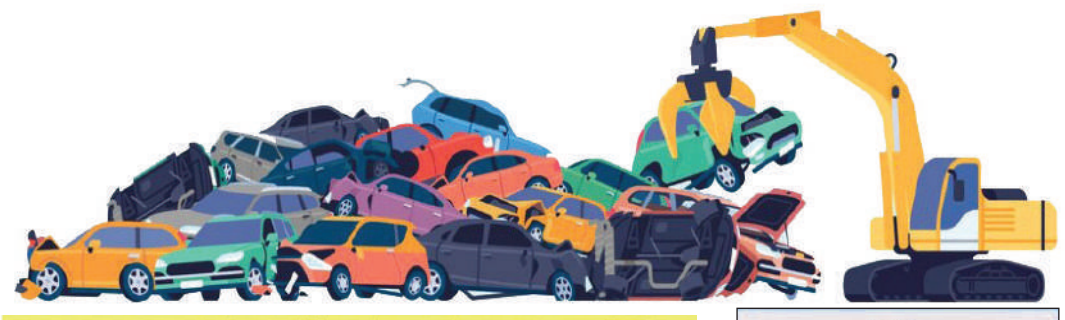

संजय बाटला

नई दिल्ली। परिवहन विभाग द्वारा अगर जल्द स्क्रैप पालिसी में घोषित निर्धारित समय सीमा समाप्त कर चुके व्यवसायिक वाहनों के लिए एनओसी जारी करना शुरु नही किया तो वाहन मालिक झुट्ठी और गुमराह करने वाली एस.ओ.पी. जारी करने के आधार पर उच्च न्यायालय में परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिको को परेशान करने और उच्च न्यायालय को गुमराह करने के लिए रिट याचिका दाखिल करेंगे और इसमें नामजद परिवहन विभाग दिल्ली, विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम, स्क्रैप शाखा परिवहन विभाग, प्रवर्तन शाखा परिवहन विभाग को वादी बनाएंगे और न्यायलय से न्याय और गलत और झुठी एसओपी जारी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की करेंगे मांग। उच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला आज दिनांक 4 अप्रैल 2014 को विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम से परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के मिलने के बाद बैठक में लिया गया क्योंकि कल 3 अप्रैल 2014 को टोलवा की बैठक में विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम द्वारा आज से निर्धारित समय सीमा समाप्त कर चुके व्यवसायिक वाहनों के लिए एनओसी जारी करवाने की बात कही गई थी पर आज वह अपनी बात से स्वयं बदल गए। इसका मतलब वह पहली की तरह ही अपने पद के बल का प्रयोग कर वाहनों को उठवाकर अपने प्रिय वाहन स्क्रैप डीलरो को सुपुर्द करने की इच्छा रखते हैं।

अब जाने क्या हुआ आज की बैठक में : विशेष परिवहन आयुक्त से आज परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के संपादक मिले और उनसे जानना चाहा कि किस आधार पर विशेष परिवहन आयुक्त ने व्यवसायिक वाहन जिस की निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी थीं ऐसे मात्र एक व्यवसायिक वाहन को एनओसी जारी करी और अन्य सभी व्यवसायिक वाहनों के लिए उसे रोक रखा है। संपादक द्वारा उन्हे उन्ही के द्वारा जारी स्क्रैप पालिसी एस.ओ.पी. की भी याद करवाई गई जिसमे परिवहन विभाग ने वाहन की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के 90 दिन बाद तक एनओसी के लिए अप्लाई करने की बात कही है और इसके साथ ही एनजीटी, उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा भी उन वाहन मालिको को जो एनओसी प्राप्त करना चाहते हैं को एनओसी जारी करने की बात कही है। सब कुछ जानते हुए भी विशेष परिवहन आयुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया और यह कह कर बात खत्म कर दी की सोच कर निर्णय लेकर बता देंगे। **अब प्रश्न यह उठता है कि किस आधार पर विशेष परिवहन आयुक्त दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिकों के वाहनो की एनओसी जारी होने से रुकवा रहे हैं ओर क्यों नही जारी करना चाहते ?**

सरकारी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के परिवहन विभाग, प्रवर्तन शाखा, 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली-110054

ईओ/मुख्यालय/ईएनएफ/टीपीटी/2024/19124
परिपत्र :- दिनांक: 19 मार्च 2024

विशेष आयुक्त (एन.एफ.) के निर्देशों के अनुसार, सभी प्रवर्तन क्षेत्र की टीमों को नीचे दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाता है:-

1. छत पर अधिक भार ले जाने वाले माल/यात्री वाहनों पर धारा 93(8) सीएमवीआर/194(1ए) एमवी अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने वाली सभी प्रवर्तन क्षेत्र टीमें अतिरिक्त भार के साथ-साथ मौके पर ही वाहन की कुल वास्तविक ऊंचाई को मापेंगी। उस वाहन का चालान बनाते समय छत तथा टिप्पणी में स्पष्ट उल्लेख करें।

2. इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक क्रमांक. ईओ/मुख्यालय/टीपीटी/ईएनएफ/2023/103222 दिनांक 09/11/2023, बस भीड़ ड्यूटी में तैनात सभी प्रवर्तन क्षेत्र की टीमें दैनिक आधार पर कम से कम पांच बसों को हिरासत में लेंगी जो माल की ओवरलोडिंग कर रही हैं।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।

यह SCOT (Enf.) के पूर्व अनुमोदन से जारी किया गया है।

प्रवर्तन अधिकारी

जानकारी के लिए प्रतिलिपि:-

1. पीए से स्कॉट (एन.एफ.)
2. पीए से डीसी (एन.एफ.)
3. सभी संबंधित जोनल इंस्पेक्टर (एन.एफ.) उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे

पर्यवेक्षण के अपने संबंधित क्षेत्र के तहत टीमों द्वारा।

4. समस्त टीम प्रभारी
5. प्रभारी नियंत्रण कक्ष सभी प्रवर्तन क्षेत्र टीमों को सूचित करेगा।

यह छूट हटने के बाद से वरिष्ठ नागरिकों को अन्य यात्रियों के समान ही किराया देना होता है।

बुजुर्ग यात्रियों से किराए में छूट वापस ले रेलवे ने 4 साल में कमाए 5,800 करोड़ से अधिक

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ट्रेन किराये में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें वापस लेने के बाद से भारतीय रेल ने बुजुर्गों से 5,800 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त राजस्व कमाया है। प्राप्त खबरों के अनुसार सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत पूछे गए सवालों से इसका पता चला है। रेल मंत्रालय ने 20 मार्च, 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण देशभर में लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराये में दी जाने वाली छूट वापस ले ली थीं। उस समय तक रेलवे महिला यात्रियों को ट्रेन किराये में 50 फीसदी और पुरुष तथा ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों को 40 फीसदी की छूट देता था।

यह छूट हटने के बाद से वरिष्ठ नागरिकों को अन्य यात्रियों के समान ही किराया देना होता है। रेलवे मानदंडों के अनुसार, 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुष और ट्रांसजेंडर और 58 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र की महिलाएं वरिष्ठ नागरिक मानी जाती हैं। बुजुर्गों को यात्री किराये में दी जाने वाली छूट खत्म होने के बाद की स्थिति के बारे में तस्वीर कुछ आरटीआई आवेदनों पर आए जवाबों से स्पष्ट हुई है।

मध्य प्रदेश निवासी चंद्र शेखर गौड़ ने अलग-अलग समय पर आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन दायर कर जानकारी निकाली है कि 20 मार्च, 2020 से 31 जनवरी, 2024 तक रेलवे ने इस मद में 5,875 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त राजस्व कमाया है।

गौड़ ने कहा, 'मैंने आरटीआई अधिनियम के तहत तीन आवेदन दायर किए। पहले आवेदन में रेलवे ने मुझे 20 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 तक का अतिरिक्त राजस्व आंकड़ा मुहैया कराया। दूसरे आवेदन में एक अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक का आंकड़ा सामने आया। वहीं फरवरी,

2024 में दाखिल तीसरे आवेदन से मुझे एक अप्रैल, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक का ब्योरा मिला।'

उन्होंने इन आरटीआई जवाबों की प्रतियां साझा करते हुए कहा, 'रेलवे ने वर्ष और लिंग के आधार पर आंकड़े दिए हैं। इनके सहारे हम 20 मार्च, 2020 से 31 जनवरी, 2024 तक रेलवे की ओर से एकत्र किए गए अतिरिक्त राजस्व का आसानी से पता लगा सकते हैं।'

इन प्रतियों से पता चलता है कि लगभग चार साल की अवधि में लगभग 13 करोड़ पुरुष, नौ करोड़ महिला और 33,700 ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों ने लगभग 13,287 करोड़ रुपये का कुल राजस्व देकर ट्रेन यात्राएं कीं।

गौड़ ने कहा, 'महिलाओं के लिए 50 फीसदी और पुरुष एवं ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिक यात्रियों के लिए पहले लागू 40 फीसदी रियायत की गणना करने पर यह राशि 5,875 करोड़ से अधिक बैठती है।'

महामारी के बाद खत्म कर दी गई छूट

वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किरायों में मिलने वाली रियायत महामारी खत्म होने के बाद बहाल किए जाने से जुड़े सवाल संसद के दोनों सदनों समेत विभिन्न मंचों पर उठाए जा चुके हैं। हालांकि, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका कोई सीधा जवाब न देते हुए कहा था कि भारतीय रेलवे प्रत्येक रेल यात्री को ट्रेन किराये पर 55 फीसदी छूट देता है।

वैष्णव ने जनवरी, 2024 में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था, 'अगर किसी गंतव्य के लिए ट्रेन टिकट की कीमत 100 रुपये है तो रेलवे यात्री से केवल 45 रुपये ही वसूल रहा है। इस तरह यात्रा पर 55 रुपये की रियायत दे रहा है।'

इस संदर्भ में गौड़ ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कोई नई पेशकश करने के बजाय केवल रियायतें वापस ली हैं। लिहाजा इससे पता चलता है कि कोविड-19 से पहले ट्रेन टिकट की खरीद पर 55 रुपये की तुलना में अधिक रियायत दी जा रही थीं।

फोरलेन हाईवे निर्माण के दौरान टूटा ब्रिज का गार्डर....

बनने से पहले ही गार्डर के टूटने को लेकर हाईवे निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। काशीपुर हरिद्वार फोरलेन हाईवे निर्माण के दौरान पूर्वी गंग नहर के ब्रिज का गार्डर दो टुकड़ों में टूटकर विभाजित हो गया। गार्डर टूटते ही मौके पर काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। मजदूरों ने किसी तरह मौके से भाग कर अपनी जान बचाई। बनने से पहले ही गार्डर के टूटने को लेकर हाईवे निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल काशीपुर से हरिद्वार को जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे- 74 पर 4 लेन सडक का निर्माण कार्य चल रहा है। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में जिस समय हरिद्वार काशीपुर फोरलेन सरवनपुर गंग नहर के पुल पर गार्डर रखने का काम किया जा रहा था तो इस दौरान अचानक गार्डर दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। हादसा होते ही मौके पर काम कर रही निर्माण यूनिट में हड़कंप मच गया। गार्डर टूटने से बुरी तरह घबराए मजदूरों ने किसी तरह मौके से भाग कर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि गार्डर टूटने के बाद निर्माण इकाई ने रातों-रात गैस कटर से गार्डर को दो टुकड़ों में काटकर अलग-अलग करके हटाते हुए मामले पर लीपा पोती का प्रयास किया है।

प्रतिमा और प्रति 'माँ' में हैं आदिशक्ति जगतजननी मां दुर्गा

वरिष्ठ समाजसेवी डॉ उमेश शर्मा

माँ जगदंबा की कृपा से संपूर्ण विश्व में सद्भावना का संचार हो और माँ का आशीर्वाद चराचर जगत पर सदैव बना रहे

नवरात्रि के नौ दिन बहुत ही पावन माने जाते हैं। चैत्र नवरात्र के दौरान माता के नौ रूपों की पूजा होती है। इस साल मंगलवार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जो कि 17 अप्रैल तक रहेगी। इस चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आ रही है। माता रानी की नौ दिन अपने भक्तों के बीच रहकर उनकी हर परेशानी दूर करती है। यहीं कारण है कि पहले दिन घटस्थापना से लेकर आखिरी दिन राम नवमी तक हर दिन बहुत खास माना जाता है। हर दिन देवी दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है, जिसमें उनके अवतारों का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति और गुणों की पूजा की जाती है।

आगामी चैत्र नवरात्र के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली मातृशक्ति के सम्मान में अपने विचार व्यक्त करते हुऐ वरिष्ठ समाजसेवी डॉ उमेश शर्मा ने कहा कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।। आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना के महापर्व चैत्र नवरात्रि की इस साल मंगलवार 9 अप्रैल से शुरुआत हो रही है, जो कि 17 अप्रैल तक रहेगी। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों का महापर्व है, जिसमें 9 दिनों तक अलग-अलग देवियों की पूजा की जाती है। इन्हें महाशक्ति कहा गया है। नवरात्रि के 9 तीन हिंदू देवियों-पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के नौ विभिन्न स्वरूपों की उपासना के लिए निर्धारित है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। पहले तीन दिन पार्वती के तीन स्वरूपों, अगले तीन दिन लक्ष्मी मां के स्वरूपों और आखिरी के तीन दिन देवी माँ सरस्वती के स्वरूपों की पूजा करते हैं। वर्ष में दो वार शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती दुर्गा के अनुष्ठान आयोजित होते। यह मातृशक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय के मन में विश्वास और सम्मान का प्रतिक हैं। भारतीय परम्परा में नवरात्रि का आयोजन देवी के नौ स्वरूपों के माध्यम से शक्ति, ज्ञान तथा ऐश्वरय के तीन महत्वपूर्ण पक्षो को प्रगट करता हैं। आदिशक्ति जगत जननी मां दुर्गा प्रतिमा और प्रति माँ में हैं। इसलिए समाज में देवी की प्रतीक महिलाओं के सम्मान के कार्यों को आगे बढ़ाएं, तो वे समाज में नई प्रेरणा बनेंगे। यह कार्य आधी आबादी को स्वावलम्बन की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। यह समाज व हम सब की जिम्मेदारी है और चैत्र नवरात्र भी जीवन में हमें इस बात की प्रेरणा देते है कि कोई भी कार्य असम्भव नहीं है, बस बेहतर प्रयास की आवश्यकता है। प्रत्येक क्षेत्र में सम्भावनाएं हैं। उन सम्भावनाओं को समय से चुनते हुए कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यह सभी कार्य एक सुरक्षित वातावरण में ही सम्भव हैं। इसी विचार के साथ जगज्जननी मां दुर्गा आदिशक्ति माँ भगवती के सभी रूपों की आराधना-उपासना के महापर्व चैत्र नवरात्रि की सभी को अग्रिम हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जगज्जननी की कृपा सम्पूर्ण विश्व पर बनी रहे और चहुंओर आरोग्यता, खुशहाली और समृद्धि हो माँ भगवती से यही प्रार्थना है। मां अंबे की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे। शक्ति स्वरूपा माता जगदंबा की अनुकंपा से सभी का जीवन सुख, शांति एवं आरोग्यता से परिपूर्ण हो। सुख, शांति और समृद्धि की मंगलमय कामनाओं के साथ आप और आप के परिवार को चैत्र नवरात्रि की अग्रिम हार्दिक मंगल कामनाएं। मां अम्बे आपको और आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, वैभव और यश प्रदान करें, मां जगदंबा की कृपा से संपूर्ण विश्व में सद्भावना का संचार हो और जगज्जननी की कृपा चराचर जगत पर बनी रहे, चहुंओर आरोग्यता, खुशहाली और समृद्धि हो, आदिशक्ति माँ भगवती से यही प्रार्थना है।

> “ नवरात्रि के 9 तीन हिंदू देवियों-पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के नौ विभिन्न स्वरूपों की उपासना के लिए निर्धारित है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। पहले तीन दिन पार्वती के तीन स्वरूपों, अगले तीन दिन लक्ष्मी मां के स्वरूपों और आखिरी के तीन दिन देवी माँ सरस्वती के स्वरूपों की पूजा करते हैं।

इस संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ - शुभ और मंगल में हैं, वह सब माँ भगवती की विभूति हैं

चहुंओर आरोग्यता, खुशहाली और समृद्धि हो, आदिशक्ति माँ भगवती से यही हमारी प्रार्थना

समाजसेवी पंकज जैन

चैत्र नवरात्रि के नौ दिन हिंदू धर्म में अत्यधिक धार्मिक महत्व रखते हैं। नौ दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्र के दौरान प्रतिदिन मां भगवती के अलग-अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में आती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 से 17अप्रैल रहेगी। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, नवरात्रि उत्सव के नौवें दिन ही राम नवमी मनायी जाती है। इसी वजह से चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है।

आगामी चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर समाजसेवी पंकज जैन ने माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना कर माँ से देश में सुख, शांति और समृद्धि एवम्विश्व कल्याण की कामना करते हुए बताया कि मां जगत जननी जगदम्बा की एकाग्रता के माध्यम से मां के शरणागत रहते हुए जीवन को सफल बनाने के लिए चैत्र नवरात्र सर्वोत्तम पर्व है। जब कभी भी पृथ्वी पर असुरीशक्तियों का अत्याचार बढ़ता है तब मां भगवती ने किसी न किसी रूप में अवतरित होकर मानव जाति का कल्याण करती है। जगत जननी मां जगदंबा की शक्ति और भक्ति व्यक्ति के जीवन को भवसागर से पर लगती है। मां दुर्गा की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। चैत्र नवरात्र पर्व के दौरान सात्विक मन से की गई मां भगवती की आराधना सहस्त्र गुना पूर्ण फलदाई होती है। इस संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ - शुभ और मंगल में है। वह सब मां भगवती की विभूति है। मां जगत जननी जगदम्बा दया एवं करुणा का सागर है, जो भक्तों की सूक्ष्म आराधना से ही प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। जगत का कल्याण करने वाली मां भगवती की आराधना से व्यक्ति में उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। मां शक्ति की पूजा के लिए नवरात्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नवरात्रों में माँ भगवती की आराधना से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। मां भगवती की आराधना सभी भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। नवरात्रों में प्रतिदिन मां भगवती के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करना करने से भक्तों के सभी कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती है। चैत्र नवरात्रि पर आराधना करने से मां भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां भगवती की कृपा से भाग्य प्रबल होता है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रों में नौ दिन तक की गई आराधना से प्रसन्न होकर मां भगवती भक्तों के भंडार भर देती है। मां दुर्गा अपने भक्तों का कष्ट दूर कर जीवन में खुशहाली स्थापित करती है और समय-समय पर मां दुर्गा अलग-अलग स्वरूपों स्वरूप धारण कर भक्तों की रक्षा करती हैं। नवरात्रि के नौ दिनों में भक्तों द्वारा श्रद्धा समर्पण भाव से मां दुर्गा की पूजा आराधना करने से मां भगवती लोक कल्याण करती है और जीवन में शांति स्थापित करती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मां भगवती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर हम मां जगत जननी से देश - प्रदेश की सुख समृद्धि व जीव मात्र के कल्याण की कामना करते हैं।माँ जगज्जननी दुर्गा आदिशक्ति माँ भगवती के सभी रूपों की आराधना - उपासना के महापर्व चैत्र नवरात्रि की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जगज्जननी की कृपा सम्पूर्ण विश्व पर बनी रहे। माँ जगत जननी जगदम्बा सभी को अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, वैभव और यश प्रदान करें, और चहुंओर आरोग्यता, खुशहाली और समृद्धि हो। मां अंबे की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे।शक्ति स्वरूपा माता जगदंबा की अनुकंपा से सभी का जीवन सुख, शांति एवं आरोग्यता से परिपूर्ण हो। माँ जगत जननी जगदम्बा से यही हमारी प्रार्थना है। मां जगदंबा की कृपा से संपूर्ण विश्व में सद्भावना का संचार हो और जगज्जननी की कृपा चराचर जगत पर बनी रहे, चहुंओर आरोग्यता, खुशहाली और समृद्धि हो, आदिशक्ति माँ भगवती से यही हमारी प्रार्थना है।

> नवरात्रों में माँ भगवती की आराधना से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। मां भगवती की आराधना सभी भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। नवरात्रों में प्रतिदिन मां भगवती के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करना करने से भक्तों के सभी कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती है। चैत्र नवरात्रि पर आराधना करने से मां भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां भगवती की कृपा से भाग्य प्रबल होता है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रों में नौ दिन तक की गई आराधना से प्रसन्न होकर मां भगवती भक्तों के भंडार भर देती है।

बात-बात पर पार्टनर से चिढ़ जाते हैं, आ जाता है गुस्सा? जानें क्या चीज आपको कर रही है ट्रिगर

एकता

पिछले अनुभवों, अधूरी जरूरतों या अनसुलझे मुद्दों की वजह से हम ट्रिगर हो जाते हैं। बार-बार और बात-बात पर ट्रिगर होना रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ट्रिगर्स को पहचानने और समझने की कोशिश करें। पता लगाएं कि क्या चीजें आपको परेशान कर रही है जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो रहे हैं ताकि आप इन्हें बेहतर तरीके से संबोधित कर पाएं।

रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, जो हमारी गहरी भावनाओं और छोटी-बड़ी कमजोरियों को दर्शाते हैं। कभी-कभी हम कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, जो हमारे अंदर तीव्र भावनाएँ पैदा कर देती है। इनकी वजह से अक्सर हम कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं। ऐसी प्रतिक्रियाएं हमारे रिश्ते पर गहरे घाव छोड़ देती हैं। इन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को ₹ट्रिगर₹ कहा जाता है। हम अक्सर रिश्ते में ट्रिगर महसूस करते हैं। लेकिन क्यों? पिछले अनुभवों, अधूरी जरूरतों या अनसुलझे मुद्दों की वजह से हम ट्रिगर हो जाते हैं। बार-बार और बात-बात पर ट्रिगर होना रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ट्रिगर्स को पहचानने और समझने की कोशिश करें। पता लगाएं कि क्या चीजें आपको परेशान कर रही है जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो रहे हैं ताकि आप इन्हें बेहतर तरीके से संबोधित कर पाएं। चलिए आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताते हैं, जिनकी वजह से अक्सर लोग ट्रिगर हो जाते हैं।

रिलेशनशिप कोच मार्लेना टिलहोन ने कुछ कारण साझा किए कि क्यों हम किसी रिश्ते में ट्रिगर महसूस करते हैं-

अपमानित महसूस करने की वजह से

अच्छे और हेल्दी रिश्ते के लिए सम्मान सबसे जरुरी होता है। अगर आपका पार्टनर आपको बार-बार अपमानित कर रहा है या आपको दबा रहा है तो आपका ट्रिगर होना जायज है। लेकिन बार-बार ट्रिगर होना आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आपका पार्टनर बार-बार आपको अपमानित कर रहा है तो रिश्ते से बाहर निकलना आपके लिए बेहतर रहेगा।

ध्यान न देना या परवाह न करने की वजह से

रिश्ते में हमें अपने पार्टनर की देखभाल करनी पड़ती है। हमें अपने पार्टनर का और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। इन्हीं चीजों की हम अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं। ऐसे में अगर पार्टनर हमारी परवाह करना बंद कर दें या हम पर ध्यान न दें तो हम ट्रिगर हो जाते हैं। ट्रिगर होने की वजह से अक्सर हम लड़ाई-झगड़ों पर उतर आते हैं, जो रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है।

डरा हुआ महसूस करने की वजह से

बहुत से लोग अपने पिछले रिश्तों के बुरे अनुभव दिल में दबाकर रखते हैं। इन बुरे अनुभवों का असर लंबे समय तक दिखता है। ये हमारे नए रिश्ते पर असर डालते हैं। हमें अक्सर छोड़े जाने का डर सताता रहता है। इसलिए हमारे पार्टनर के व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव आते ही हम डर जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। ये चीजें हमें बुरी तरह ट्रिगर करती हैं।

भगवान शंकर श्रीराम जी की कथा श्रवण करते-करते क्यों रो पड़ते थे?

भगवान शंकर जब सतीजी को अगस्त्य मुनि जी के आश्रम में लेकर चलते हैं, तो साथ मे सतीजी भी बड़े चाव से उनके आश्रम चलती हैं। उनके मन में अगस्त्य मुनि के प्रति श्रद्धा, सम्मान व प्रेम सब कुछ है। यहाँ सतीजी के हृदय के भाव भगवान शंकर से पूर्णत: मेल खाते हैं।

विगत अंक में हमने जाना था, कि भगवान शंकर आदिशक्ति सतीजी के साथ, अगस्त्य मुनि जी के आश्रम से वापिस कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने सतीजी के लिए जो शब्द प्रयोग किए, वे उनके दैवीय प्रभाव के अनुकूल नहीं थे। कारण कि, भगवान शंकर जब अगस्त्य मुनि के आश्रम में गये थे, तो गोस्वामी जी सतीजी के लिए 'जगत जननी' जैसे पूजनीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं-

'संग सती जगजननि भवानी।
पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी।।'

वहीं जब सतीजी, जब अगस्त्य मुनि के आश्रम से वापिस कैलास को जाने लगीं, तो गोास्वामी जी इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं-

'मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी।
चले भवन सँग दच्छकुमारी।।'

अर्थात भगवान शंकर के साथ अब जगत जननी नहीं, अपितु दक्षसुता जा रही हैं।

गोस्वामी जी के इन शब्दों के अर्थ बड़े मार्मिक हैं। आखिर क्या ही अंतर पड़ जायेगा, अगर भगवान शंकर की पत्नी कहने की बजाये, दक्ष कन्या कह दिया जायेगा? यह समझने के लिए हमें देवतायों के गुरु प्रजापति दक्ष की, भगवान शंकर जी के प्रति भावना देखनी पड़ेगी। यह वही दक्ष हैं, जिन्होंने सतीजी को भगवान शंकर के साथ परिणय सूत्र में बँधने में लाख रोड़े अटकाये थे। यह वही दक्ष हैं, जिन्होंने कहा था, कि भगवान शंकर में कोई गुण नहीं, वे निर्गुणी हैं। मैं उन्हें देवों के देव मानने के लिए सहमत नहीं हूं। भगवान तो उन्हें मैं किसी भी आधार पर नहीं मान सकता।

प्रश्न उठता है, कि पिता दक्ष के इतना विरोध करने पर भी, सतीजी ने भगवान शंकर को ही पति रुप में क्यों चुना। कारण स्पष्ट था, कि सतीजी शिवजी को केवल एक अघौड़ी नहीं, बल्कि भगवान मानती थी। दक्ष का स्वभाव है, कि वह भगवान शंकर से विपरीत चलता है। वहीं सतीजी का मत ही यह है, कि वह सदा भगवान शंकर के मतानुसार चले।

भगवान शंकर जब सतीजी को अगस्त्य मुनि जी के आश्रम में लेकर चलते हैं, तो साथ मे सतीजी भी बड़े चाव से उनके आश्रम चलती हैं। उनके मन में अगस्त्य मुनि के प्रति श्रद्धा, सम्मान व प्रेम सब कुछ है। यहाँ सतीजी के हृदय के भाव भगवान शंकर से पूर्णतः मेल खाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, कि भगवान शंकर के साथ जगत जननी भी हैं। लेकिन अवश्य ही अगस्त्य मुनि जी के आश्रम में ऐसा कुछ तो घटा है, कि सतीजी न ही तो अगस्त्य मुनि जी के मुख से प्रस्फुटित हो रही श्रीराम कथा सुनती हैं, और न ही उतने दिन उनका मन आश्रम में लगता है। सतीजी को कोई वास्ता ही नहीं था, कि अगस्त्य मुनि कथा में क्या प्रसंग कह रहे हैं, या क्या कहना चाह रहे हैं। उन्हें तो मानों तब तक आश्रम में रुकना था, जब तक भगवान शंकर आश्रम में रुके हैं।

ऐसा नहीं कि सतीजी अगस्त्य मुनि के समक्ष कथा सुनने के लिए, भगवान शंकर के साथ नहीं बैठती थी। बैठती तो थी, लेकिन उनका मन कहीं ओर विचरण करता रहता था। दूसरी ओर भगवान शंकर श्रीराम जी की कथा श्रवण करते-करते, कितने ही बार रो भी पड़ते थे। सतीजी भी भगवान शंकर को यूँ रोते देखती, तो सोचती, कि इसमें भला रोने वाली क्या बात है? क्या कोई कहानी सुन कर भी रोता है? लेकिन भगवान शंकर जैसे-जैसे कथा सुनते, उनका हृदय श्रीराम जी के दर्शनों को लेकर और व्यग्र हो उठता। उनका रोम-रोम प्रभु के श्रीचरणों में नमस्कार करने हेतु ललायत होने लगाता।

अरविंद केजरीवाल कैसे चला सकते हैं जेल से सरकार, एक्सपर्ट ने बताए नियम से लेकर विकल्प तक

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें सरकार चलाने में कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं है अब वह न्यायिक हिरासत में हैं तो सभी कुछ अदालत पर निर्भर है। इसी को लेकर संवाददाता ने राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण से बात की और यह जानने की कोशिश की है कि सीएम के पास क्या विकल्प हैं नियम क्या कहते हैं...

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में चल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। जेल जाने के बाद भी केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी का शुरू से ही ये स्टैंड रहा है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वह जेल से ही सरकार चलाएंगे।

हालांकि इस पर नियम और विकल्प क्या कहते हैं यह ज्यादा मायने रखता है। इसी को लेकर जागरण संवाददाता वीके शुक्ला ने राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण ने बात की और यह जानने की कोशिश की है कि दिल्ली सीएम के पास क्या विकल्प हैं और नियम क्या कहते हैं...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें सरकार चलाने में कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं है, अब वह न्यायिक हिरासत में हैं तो सभी कुछ अदालत पर निर्भर है।

सब अदालत पर है निर्भर

वह जेल से सरकार चला सकते हैं या उन्हें जेल में कार्यालय मिल सकता है या वे जेल से फाइलें पढ़कर साइन कर भेज सकते हैं। अब यह सब अदालत पर निर्भर करेगा।

जेल में सुविधाओं की बात करें तो जेल में उन्हें भी अन्य कैदियों की तरह भोजन व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। वह अदालत से अपने लिए मांग कर सकते हैं, घर का खाना आदि की मांग कर सकते हैं।

जेल मैनुअल में छूट के लिए एलजी से कर सकते हैं निवेदन

जहां तक जेल मैनुअल में उन्हें छूट की बात है तो यह सब एलजी पर निर्भर करेगा। वह एलजी से निवेदन कर सकते हैं।

अब अगर हम इस बात पर आते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों खड़ी हुई है। यह साफ है कि यह देश में ही पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल गया है।

मेरा मानना है कि अगर किसी नेता को इस तरह के किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जमानत नहीं मिलती है, तो यह बात तो साफ है कि अदालत ने उसे इस लायक नहीं माना है।

कानून नहीं कहता कि दें इस्तीफा

कुछ गड़बड़ पाई है कि जमानत नहीं दी है और जेल भेज दिया है। ऐसे में नैतिक आधार पर संबंधित व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर ऐसा किया गया होता तो यह समस्या सामने नहीं आती।

ताजा मामला झारखंड का भी है जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया और वहां किसी और सदस्य को मुख्यमंत्री बना दिया गया।

देखिए, कानून यह नहीं कहता है कि ऐसे मामले में इस्तीफा देना चाहिए, मगर नैतिकता भी कोई चीज होती है। उसका हमें सम्मान करना चाहिए।

ये है सबसे सुविधाजनक विकल्प

राज्यसभा के पूर्व महासचिव कहते हैं कि जहां तक मौजूदा स्थिति में सरकार को चलाने की बात है तो उसका एक विकल्प यह भी है कि सरकार में एक उपमुख्यमंत्री बना दिया जाए और उनके माध्यम से फाइलें चलाई जाएं।

फाइलों को अनुमति देकर एलजी के पास भी स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं और सरकार को चलाने में भी असुविधा नहीं होगी।

सरकार की फाइलें, महत्वपूर्ण कार्य कैबिनट की बैठकें आदि आसानी से होती रहेंगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का यह पहला मामला है।

अगर अदालत ने दी अनुमति तो...

अब यह सब अदालत पर ही निर्भर है कि वह जेल में कैबिनेट की बैठक आदि करने की अनुमति देती है या नहीं। मगर जनता के काम भी नहीं रुकने चाहिए, अगर अदालत में इस सब को करने की अनुमति नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है कि जनता के काम रुकेंगे, क्योंकि सरकार में अधिकारी और मंत्री तो काम करेंगे ही।

मगर फैसलों पर अंतिम मुहर नहीं लग सकेगी तो वह काम वहीं पर रुक जाएगा। इसलिए इस बारे में सोचना जरूरी है और इस समस्या का समाधान

'हम नहीं कर सकते समाधान, आप LG के पास जाइए', CM पद से केजरीवाल को हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का विचार से इनकार

दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग संबंधी याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि कई बार राष्ट्रीय हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखना पड़ता है। यह कानून की अदालत है और हमें कानून के अनुसार चलना होगा। इस मामले का समाधान अदालत नहीं कर सकती है।

नई दिल्ली। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाने की मांग से जुड़ी याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि कई बार राष्ट्रीय हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखना पड़ता है। अदालत ने कहा कि यह कानून की अदालत है और हमें कानून के अनुसार चलना होगा। इस मामले का समाधान अदालत नहीं कर सकती है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को उचित फोरम पर जाना होगा।

हिंदू सेना अध्यक्ष ने याचिका ले ली वापस

पीठ ने कहा कि ऐसे बिंदुओं से एक याचिका को अदालत पूर्व में खारिज कर चुकी है और अब वह इस मामले में अलग दृष्टिकोण नहीं रख सकती है। अदालत का रुख देखते हुए हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने यह कहते हुए याचिका वापस ले ली। वह इस संबंध में उपराज्यपाल के पास जाएंगे।

'सारे काम हाई कोर्ट नहीं कर सकता'

याचिका वापस लेने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा कि सारे काम हाई कोर्ट नहीं कर सकता है और यह हाई कोर्ट का काम नहीं है। अदालत ने कहा कि यह उपराज्यपाल को तय करना है और अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो जाईए। अदालत का रुख देखकर याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने याचिका वापस ली।

पहले भी ऐसी मांगें हो चुकी है खारिज

इससे पहले इन्हीं मांगों से संबंधित सुरजीत कुमार यादव की तरफ से दायर दो याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और दस दिन तक के ईडी रिमांड के बाद अदालत ने केजरीवाल को एक अप्रैल को 15 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

भगत सिंह और अंबेडकर के बीच क्यों लगी थी सीएम केजरीवाल की तस्वीर? आलोचना के बाद आप ने दिया करारा जवाब

परिवहन विशेष न्यूज

सुनीता केजरीवाल के वीडियो ब्रीफिंग के दौरान बैकग्राउंड में भगत सिंह और बीआर अंबेडकर की तस्वीर के बीच सीएम केजरीवाल की फोटो लगाने पर सोशल मीडिया पर इसकी जमकर आलोचना हो रही है। इस पर मंत्री आतिशी ने जवाब दिया और कहा कि केजरीवाल आज बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ चल रहे संघर्ष के प्रतीक हैं और उनकी तस्वीर इस बात का सबूत है।

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी गुरुवार को वीडियो ब्रीफिंग की। इस दौरान उनके बैकग्राउंड में भगत सिंह और बीआर अंबेडकर की तस्वीर के साथ अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी थी। इसके बाद बीजेपी ने इसकी आलोचना की और कहा कि केजरीवाल को भगत सिंह और अंबेडकर की बराबरी में नहीं लगाना चाहिए। वहीं इस पर आप की प्रतिक्रिया सामने आई है।

आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल आज बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ चल रहे संघर्ष के प्रतीक हैं और उनकी तस्वीर इस बात का सबूत है।

बीजेपी के खिलाफ संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम की तरह: आतिशी

आतिशी ने कहा, ₹केंद्र की बीजेपी सरकार ने झूठे आरोप में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल आज भाजपा की तानाशाही के खिलाफ चल रहे संघर्ष के प्रतीक हैं और उनकी तस्वीर इस बात का सबूत है। यह हमें याद दिलाने के लिए है कि आज भाजपा के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है, वह किसी स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। एक समय था, जब देश की जनता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती थी। आज ऐसा समय है जब हमें भाजपा की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करना है और अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं।

बता दें, अरविंद केजरीवाल की तुलना भगत सिंह और बीआर अंबेडकर से करने पर आप की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। बीजेपी ने भी आप को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता केजरीवाल की पार्टी के बहकावे में नहीं आएगी।

वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कट्टर भ्रष्ट

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर कहा, ₹भगत सिंह जी और बाबा साहेब अंबेडकर जी के बीच एक कट्टर भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाना बेहद अफसोसजनक है। पहले पति कैमरे के सामने झूठ बोलते थे। अब जेल में रहकर वह अपनी पत्नी से झूठा बयान दिला रहे हैं। जनता आप के बहकावे में नहीं आने वाली है।

जमानत मिली तो जांच बेपटरी हो जाएगी', के. कविता की बेल का ED ने किया विरोध; कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

तिहाड़ जेल में बंद तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बीआरएस नेता के कविता ने अपने बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका की मांग की थी। वह नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

नई दिल्ली। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की बेटी व भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। कविता ने अपने बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका की मांग की थी।

8 अप्रैल को आएगा फैसला

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दोनों पक्षों की दलीलें को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत इसपर आठ अप्रैल को फैसला सुनाएगी। ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा होने पर जांच बेपटरी हो जाएगी। कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछली सुनवाई में उनके द्वारा दी गई दलीलों को मुख्य जमानत याचिका में इस्तेमाल किया जाए।

उन्होंने दलील दी कि उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के प्रविधानों के तहत जमानत का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी मुवक्किल के 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में मां की उपस्थिति की उसे आवश्यकता है, चूंकि बच्चों को परीक्षा के दौरान मां का नैतिक और भावनात्मक समर्थन होता है। मां की कमी पिता या बहन या भाई द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता।

अधिवक्ता ने कहा कि बच्चे पर मां की गिरफ्तारी का गहरा असर पड़ा है। उन्होंने परीक्षा के दौरान बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा सत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा का दबाव कोई काल्पनिक घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि कविता के पति पहले से ही दिल्ली में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और बच्चा तेलंगाना में है।

ईडी ने जमानत का किया विरोध

ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पीएमएलए की धारा 45 के प्रविधानों के तहत छूट उस महिला के लिए नहीं है जो सार्वजनिक जीवन में है और राज्य की अग्रणी राजनेता है। ईडी ने कहा कि कविता के बेटे की 12 में से सात परीक्षाएं पहले ही खत्म हो चुकी हैं। ऐसा कोई सुबूत नहीं है जो बताता हो कि उनका बेटा किसी चिंता या बीमारी से पीड़ित है, ये सामान्य तर्क हैं, इसे साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं हैं। वह जवान है और अकेला नहीं है।

उसका समर्थन करने के लिए उसके पिता और भाई भी हैं। ईडी की इस दलील पर सिंघवी ने कहा कि वह एक लड़का है, आदमी नहीं है। ईडी ने कहा कि कविता इस मामले में मुख्य आरोपितों में से एक है। ईडी ने तर्क दिया कि कविता रिश्वत देने के प्रमुख संचालकों में से एक है। वह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लाभार्थी भी है। यह केवल बयानों पर आधारित नहीं है बल्कि दस्तावेज और वाट्सएप चैट पर आधारित है, सब प्रमाणित है। ईडी ने दावा किया कि कविता ने अपने खिलाफ सुबूत नष्ट कर दिए, जिसमें उनके मोबाइल फोन के सुबूत भी शामिल हैं।

ईडी ने कहा कि उसके पास फारेंसिक रिपोर्ट है जो दिखाती है कि सुबूत कैसे नष्ट किए गए। कविता ने अपने मोबाइल फोन से सुबूत मिटा दिए। यह सब उस दिन किया गया था जब उसे समन जारी किया गया था। फेसटाइम जैसे ऐप में कोई डाटा नहीं था, 11 मार्च को कविता ने कहा कि अगली तारीख पर फोन पेश करेंगी। अगली तारीख पर उन्होंने नौ फोन पेश किए। लेकिन सबका डाटा नष्ट किया गया था। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि डाटा 11 मार्च के बाद नष्ट हुआ है।

जांच पटरी से उतर जाएगी- ईडी

अधिवक्ता ने दावा किया कि ईडी जांच के इस स्तर पर कविता को अंतरिम जमानत मिलने से जांच पटरी से उतर जाएगी। चूंकि वह बहुत प्रभावशाली हैं और लोगों को प्रभावित करेंगी। हुसैन ने यह आरोप लगाया कि कविता पहले भी गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर चुकी हैं। एक गवाह ने बताया कि उसे बयान वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था। सुबूतों को भी नष्ट किया गया है।

ईडी की एक टीम ने 15 मार्च को कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। 26 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य राजनीतिक नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल हैं।

एम्स अस्पताल में 5 साल की बच्ची के ब्रेन की होश में ही सर्जरी करने का करने का नया रिकॉर्ड बनाया है

नई दिल्ली। एम्स अस्पताल में 5 साल की बच्ची के ब्रेन की होश में ही सर्जरी करने का करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसे एम्स अस्पताल की बड़ी सफलता माना जा रहा है। गौरतलब है कि एक 5 साल की बच्ची के ब्रेन में ट्यूमर था। बच्ची के ब्रेन ट्यूमर का सफलतापूर्वक होश में ऑपरेशन करने के लिए एम्स के अस्पताल के न्यूरो एनेस्थीसिया और न्यूरो रेडियोलॉजी टीम ने ब्रेन में ट्यूमर के एमआरआई का बेहतर ढंग से निरीक्षण किया और उसके बाद एम्स अस्पताल की टीम ने बच्ची के ब्रेन के बाएं हिस्से के ट्यूमर को बच्ची को होश में ही रखकर सक्सेसफुल ब्रेन सर्जरी कर निकाल दिया है। एम्स अस्पताल की इस सर्जरी को बड़ी सफलता माना जा रहा है। यह दुनिया की मरीज को होश में रखकर की गई पहली ब्रेन सर्जरी है। बताया जाता है की बच्ची की तबीयत अब ठीक है।

अब तक कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले 450 के पार...

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

कांग्रेस से हाथ छुडाने वाले छोटे से लेकर बडे नेताओ की संख्या 450 के पार पहुंच चुकी है। इसके बावजूद कांग्रेस के धीर-धारको का मादा इतना तगडा है कि वह यह कहते नहीं थकते कि जिसको जाना है ,वह जा सकता है। उन्हें कांग्रेस पार्टी में मची भगदड का अब तक इल्म ही नहीं हुआ है, कि आखिर कांग्रेस का हाथ छुडाने वालों को ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है।

उल्लेखनीय है कि पिछले आठ सालों में 400 से ज्यादा नेताओ ने कांग्रेस का हाथ झटका है। यहां यह भी बता दें कि प्रियांका गांधी वाड्रा की एंट्री से4 साल में सिर्फ 10 बडे नेताओ द्वारा पार्टी को छोडा चुका हैं।जबकि बाद के वर्षो में 23 बडे नेताओं द्वारा कांग्रेस का हाथ झटक चुके हैं। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म् (एडीआर) ने सितंबर 2021 में नेताओ के दल-बदल पर एक रिपोर्ट जारी की थी।इस रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के ही सबसे ज्यादा नेताओ ने पार्टी छोडी है।साल 2014 से सितंबर 2021 तक कांग्रेस के 222 ऐसे नेताओ ने पार्टी को अलविदा कहा,जो चुनावी उम्मीदवार थे।इस दौरान कांग्रेस पार्टी के तो 177 सांसद और विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इन सात वर्षो में कांग्रेस के 399 नेताओ ने पार्टी छोडी।इस रिपोर्ट के बाद भी 16 बडे नेता अपने समर्थकों संग कांग्रेस का हाथ झटक चुके है।मतलब साफ है कि आठ वर्षों में ये संख्या तकरीबन 450 के पार पहुंच चुकी है।

कांग्रेस का हाथ छोडने वाले बडे नेताओ की फेहरिस्त में हिमंत बिस्वा सरमा, ज्योतिरादित्य सिंधिया,नारायण राणे,कैप्टन अमरेंद्र सिंह,चौधरी विरेन्द्र सिंह,कुलदीप विश्नोई, सुनील झाखड, आरपीएन सिंह,कपिल सिब्बल, जतिन प्रसाद, मिलिंद देवडा, एकनाथ शिंदे,गुलाम नवी आजाद,संजय निरुपम, जिंदल,हार्दिक पटेल,अश्विनी कुमार,अल्पेश ठाकुर, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, शत्रुघ्न सिंहा,जैसे बडे नाम शामिल है।इसके अलावा जयंती नटराजन,जीके वासन,पैसा खांडू, हेमवती नंदन बहुगुणा परिवार के लोग, रीटा बहुगुणा, समेत और भी बडी संख्या में कांग्रेस को अलविदा कर चुके हैं। हाथ को बॉय-बॉय कहने वाले सैंकडों नेताओ का मानना है कि 400 पार के आंकडे पर पहुंचाने के लिए बहुत बडा हाथ राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। राहुल गांधी के व्यवहार पर करीब -करीब सभी ने प्रश्नचिन्ह लगाते हुए उन पर सीधा निशाना साधा है। बता दें कि राजनीतिक दलों में नेताओ का आना जाना वैसे तो आम बात है। लेकिन राहुल के नेतृत्व में साल-2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओ की संख्या और पार्टी पर से उठते भरोसे का सिलसिला शुरू हुआ, वो अब तक जारी है। जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता से दूर होती कांग्रेस से मोहभंग होने लगा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओ में लगातार हार झेलने की हद के चलते उन्होंने भी किसी बडे वटवृक्ष की छांव तलाशनी शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मोदी की दी गारंटी पर अबकी बार 400 पार की दहाड के आगे मिमयाते कई पार्टयों के नेताओ को नई उपजाऊ जमीन तलाशने पर मजबूर होना पड सकता है।

लोकसभा चुनाव 2024

उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का क्या है 'भाजपा प्लान'

पश्चिमी यूपी को लेकर है खास रणनीति; ब्रजेश पाठक ने किया खुलासा

परिवहन विशेष न्यूज

लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दल चुनावी प्रचार में अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट के लिए सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही है। इस बार भाजपा सभी सीटों पर जीत की उम्मीद रख रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. ब्रजेश पाठक ने 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया है।

नोएडा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट के लिए हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में 62 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस बार भाजपा सभी सीटों पर जीत की उम्मीद रख रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. ब्रजेश पाठक इस बात से पूरी तरह इत्तफाक रखते हैं।

राष्ट्रीय लोक दल का साथ मिलने के बाद इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले बेहतर जीत का दावा कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा की क्या रणनीति रहेगी और किन चीजों को लेकर चुनौती हैं, इन्हीं सब बिंदुओं पर गौतमबुद्ध नगर के ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र चंदेल ने उत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री डॉ. ब्रजेश पाठक से बातचीत की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश।

प्रश्न : पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा की क्या खास रणनीति है?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लहर चल रही है। मैंने प्रथम चरण और तीसरे चरण की सभी सीटों का दौरा किया है। भाजपा प्रदेश की सभी 80 सीटों पर एकतरफा जीत दर्ज कर रही है। सपा गठबंधन कहीं भी लड़ाई में नहीं है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रमुख सीट गाजियाबाद से प्रत्याशी का नाम सामने आने में काफी समय लगा। टिकट क्यों बदलना पड़ा?

भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि किसे टिकट दिया। जो बेहतर कार्यकर्ता होता है उसे जनता के सामने ले जाते हैं। सभी कार्यकर्ता इससे खुश भी हैं।

आप सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। भाजपा ने ऐसी क्या रणनीति बनाई है?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जो गरीब कल्याण योजना है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है वह पार्टी को जीत दिलाएगी। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से अब तक देश के लिए जो कार्य किया है, वह जीत दिलएगी।

दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो थी देश को विकसित बनाने की। विकसित भारत का संकल्प जो नरेन्द्र मोदी ने लिया है उसके साथ सब लोग जुड़ गए हैं। जनता चाहती है कि भारत विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। भारत की जनता उनके इस संकल्प के साथ खड़ी है।

एनसीआर में जाम और प्रदूषण बड़ी समस्या है। इसको लेकर भाजपा का क्या रोडमैप है?

इसके लिए हम लोग कार्ययोजना बना रहे हैं। ठोस योजना तैयार की जा रही है। स्कूल व संस्थाएं बंद करना, वाहनों का संचालन बंद करना इससे प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

इस पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, जिससे कि जाम से लोगों को न जूझना पड़े। अन्य विकास कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के हर शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाई जाएगी।

इस बार भाजपा को रालोद का साथ मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के साथ मुस्लिमों का एक बड़ा वोट बैंक रहा है। क्या इस बार ये वोट बैंक भाजपा का साथ देगा?

मुस्लिमों का वोट बिल्कुल मिलेगा। भाजपा हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर कार्य करती है। समाज का हर वर्ग पूरी तरह भाजपा के साथ है।

टिकट वितरण के दौरान भाजपा ने इस बार कुछ लोगों के टिकट काटे हैं। इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी की बात सामने आ रही है। कहीं इससे समस्या तो उत्पन्न नहीं होगी?

कहीं भी किसी तरह का विवाद नहीं है। सभी सीटों पर सभी कार्यकर्ता और जनता परिवार की तरह एकजुट हैं। किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है।

गौतमबुद्ध नगर में भाजपा का इस बार के चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहेगा? बसपा और सपा गठबंधन दोनों के साथ मुकाबला है?

गौतमबुद्ध नगर के प्रत्याशी डॉ. महेश शर्मा एकतरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। सभी जाति और धर्मों का वोट उन्हें मिलेगा। गरीब कल्याण योजना जन-जन तक पहुंची है। नोएडा एक वर्ल्ड क्लास शहर बना है।

सपा का गठबंधन फ्लाप साबित हो रहा है। उन्हें प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। बार बार प्रत्याशियों को बदल रहे हैं। जिन प्रत्याशियों को उतार रहे हैं वह लड़ने से मना कर रहे हैं। भाजपा का जन कल्याणकारी योजना का ही नतीजा है कि जो विभिन्न राजनैतिक दलों और संस्थाओं के हैं वे बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़ रहे हैं। चार जून को 400 पार लेकर धरातल पर उतरेगा भाजपा गठबंधन।

इन 360 आवंटियों में 40 आवंटी ऐसे रहे, जिन्होंने अप्रत्याशित बोली लगाई है, जिनकी ईएमडी जब्त होनी है।

320 आवंटियों को लोकसभा चुनाव के दौरान नोएडा प्राधिकरण से जारी होगा आवंटन पत्र

परिवहन विशेष न्यूज

320 आवंटियों को लोकसभा चुनाव के दौरान नोएडा प्राधिकरण से आवंटन पत्र जारी होगा। पिछले दिनों नोएडा प्राधिकरण ने 376 आवासीय भूखंड की योजना निकाली थी। इसके लिए आवेदन करने वालों ने 16 मार्च तक ऑनलाइन बोली लगाई लेकिन उसी दिन निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई। ऐसे में आदर्श आचार संहिता लग गई।

नोएडा। आवासीय भूखंड योजना में पात्र 320 आवंटियों को उनका आवंटन पत्र लोकसभा चुनाव के दौरान ही नोएडा प्राधिकरण जारी कर सकता है। इसके लिए प्राधिकरण सीईओ डॉ लोकेश एम ने शासन को पत्र लिखकर आयोग से अनुमति मांगी है, जिससे योजना में शामिल आवंटियों को उनके भूखंड का आवंटन सौंपा जा सके। नोएडा प्राधिकरण के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, जिसमें किसी भी चुनाव के दौरान योजना के पात्र लोगों को हक दिया जाने वाला है। बता दें कि पिछले दिनों नोएडा प्राधिकरण ने 376 आवासीय भूखंड की योजना निकाली थी।

16 मार्च तक लगाई थी ऑनलाइन बोली

इसके लिए आवेदन करने वालों ने 16 मार्च तक ऑनलाइन बोली लगाई, लेकिन उसी दिन निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई। ऐसे में आदर्श आचार संहिता लग गई। इसलिए पात्र 360 आवंटियों को प्राधिकरण आवासीय भूखंड विभाग आवंटन पत्र जारी नहीं कर सका।

इन 360 आवंटियों में 40 आवंटी ऐसे रहे, जिन्होंने अप्रत्याशित बोली लगाई है, जिनकी ईएमडी जब्त होनी है। इसके लिए बोर्ड में प्रस्ताव लेकर आएगा। जिस पर प्राधिकरण में आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद फैसला लिया जाएगा, लेकिन बाकी को 320 पात्र आवंटियों को आवंटन पत्र जारी करना प्राधिकरण चाहता है। इसलिए शासन को आवंटन पत्र जारी करने की अनुमति मांगी है।

11 आवंटियों ने आवेदन के बावजूद नहीं लगाई बोली

आवासीय भूखंड योजना में 11 आवंटी ऐसे रहे, जिन्होंने योजना का लाभ उठाकर आवेदन तो किया, लेकिन वह सिंगल बिडर ही रहे। इसलिए प्राधिकरण को दो बार योजना का सात-सात दिन के आगे भी बढ़ाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद 11 आवंटियों ने आन लाइन बोली में हिस्सा नहीं लिया। एक आवंटी उच्च न्यायालय की शरण में चला गया।

लक्ष्य से 80 प्रतिशत अधिक मिला राजस्व

प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड योजना का लांच कर 750 करोड़ रुपये का बेस प्राइज रखा था। यह माना था कि इतना राजस्व आवासीय भूखंड विभाग को प्राप्त होगा, लेकिन योजना में ऑनलाइन बोली लगाकर भूखंड आवंटर कराने वालों ने प्राधिकरण को लक्ष्य के सापेक्ष 80 प्रतिशत अधिक 1327 करोड़ रुपये राजस्व दिया है। यह राजस्व केवल 320 आवंटियों से हासिल हुआ है। अभी 40 आवंटियों का मामला विचाराधीन श्रेणी में है।

आवासीय भूखंड योजना में पात्र आवंटियों को आवंटन पत्र देने के लिए शासन को पत्र लिखकर अनुमति मांगी गई है, आने पर आवंटन पत्र जारी होगा।

-डॉ लोकेश एम, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण

परिवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस को शुरुआती जांच में पता चली ये बात

मुरादनगर थाना क्षेत्र के गांव रेवड़ा रेवड़ी में दंपती व तीन वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना सोमवार देर रात की है। महिला निशा व बच्ची शालू की मौत जहर के सेवन से सामने आई है जबकि व्यक्ति अंकुर ने खुद को आग लगाई। स्वजन ने पुलिस को बिना सूचित किए तीनों का मंगलवार शाम को अंतिम संस्कार कर दिया।

गाजियाबाद। मुरादनगर थाना क्षेत्र के गांव रेवड़ा रेवड़ी में दंपती व तीन वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना सोमवार देर रात की है। महिला निशा व बच्ची शालू की मौत जहर के सेवन से सामने आई है, जबकि व्यक्ति अंकुर ने खुद को आग लगाई। स्वजन ने पुलिस को बिना सूचित किए तीनों का मंगलवार शाम को अंतिम संस्कार कर दिया। बुधवार को किसी ग्रामीण से पुलिस को सूचना मिली तो अधिकारियों ने गांव में जाकर जांच की। इसमें मौत की बात पुष्ट निकली, लेकिन मौत का कारण पता नहीं चला। स्वजन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है। पुलिस अपने स्तर पर छानबीन में जुटी है।

अचानक कमरे में लगी आग

रेवड़ा-रेवड़ी गांव के अंकुर कुमार किसान थे। घर में पत्नी निशा और तीन वर्षीय बच्ची शालू के साथ रहते थे। निशा गृहणी थी। घर में पिछले कई दिनों से कलह चल रही थी। जानकारी के मुताबिक, एक अप्रैल यानी सोमवार देर रात अंकुर, निशा व शालू कमरे में थे। अचानक कमरे में आग लग गई।

धुआं उठता देख स्वजन व आसपास के लोग दौड़े और आग बुझाई। आग की चपेट में आकर अंकुर बुरी तरह झुलस गए। जबकि निशा व शालू बेहोशी की हालत में थे। उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। स्वजन व आसपास के लोग तीनों को अस्पताल लेकर पहुंचे।

महिला और बेटी के मुंह से निकल रहे थे झाग

धुआं उठता देख स्वजन व आसपास के लोग दौड़े और आग बुझाई। आग की चपेट में आकर अंकुर बुरी तरह झुलस गए। जबकि निशा व शालू बेहोशी की हालत में थे। उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। स्वजन व आसपास के लोग तीनों को अस्पताल लेकर पहुंचे।

अस्पताल रेफर किए गए तीनों

निशा व शालू को मोदीनगर के अस्पताल में मृत घोषित किया, जबकि अंकुर को मेरठ के अस्पताल रेफर किया गया। निशा व शालू का शव गांव पहुंचा ही था, इस बीच सूचना मिली कि उपचार के दौरान अंकुर की भी मौत हो गई है। रात में ही तीनों के शव गांव पहुंच गए। घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। मंगलवार को गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बुधवार को एसीपी मसूरी नरेश कुमार व थाना प्रभारी मुकेश सोलंकी गांव पहुंचे और छानबीन की। मृतक के स्वजन व गांवों के लोगों से पूछताछ की गई। इस दौरान पुलिस को घटना के साक्ष्य मिले। डीसीपी ग्रामीण ने बताया कि पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन में जुटी है।

यहां के वोटरों ने हरपाल को छोड़ कभी किसी को दोबारा सांसद नहीं चुना

अजय कुमार

कैराना लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। आगामी 19 अप्रैल को इस सीट पर मतदान होगा। जिसकी तैयारी में सभी दलों के पदाधिकारी भी लगे हुए हैं। 2024 का रण अनौपचारिक तौर पर सज चुका है।

राजनीतिक रूप से कैराना हसन परिवार और बाबू हुकुम सिंह के परिवार का गढ़ रहा है। कैराना के राजनीतिक माहौल को वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे में बदल दिया। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की लहर चली और 2014 में भाजपा के हुकुम सिंह 2.36 लाख वोटों से चुनाव जीते, जो अब तक का यहां का सबसे बड़ा अंतर है। वर्ष 2015 में कैरना के तत्कालीन सांसद बाबू हुकुम सिंह ने अपराधीकरण की वजह से शामली से व्यवसायियों के पलायन का मुझ उठाया था, जिस पर सियासत खूब गरमाई थी।

लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कभी बीजेपी के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय हुकुम सिंह की कर्मभूमि और पलायन के मुद्दे से देशभर में चर्चाओं में आई कैराना लोकसभा सीट पर इस बार भी सबकी नजर हुई है। कैराना लोकसभा सीट का महाभारत काल से पौराणिक जुड़ाव भी है. यहां के लोग मानते आ रहे हैं कि महाभारत काल में अंगराज कर्ण ने इसे कर्णनगरी के रूप में बसाया था। आजादी की लड़ाई में कैराना देशभक्तों की शरणस्थली रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले मराठों को छुपने के लिए कैराना ने जगह दी थी। कैराना वह इलाका है जहां उस्ताद अब्दुल करीम खां के जरिए संगीत के किराना घराने की शुरुआत हुई थी। वह घराना जिसने देश में खयाल गायकी को एक नया रंग दिया था। भीमसेन जोशी इसी घराने के शार्गिद थे, जिन्होंने 'मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा' को आवाज दी थी। 2019 के आम चुनाव में यहां से बीजेपी जीती थी। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा हैं। हसन परिवार की बेटी इकरा हसन के सामने इस बार जहां विरासत को बचाना चुनौतीपूर्ण है। वहीं सांसद प्रदीप चौधरी को जनता दल के लगातार दो बार सांसद रहे हरपाल सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर भाजपा को जीत दिलाना आसान नहीं होगा। वहीं पहली बार चुनाव लड़ रहे बसपा के प्रत्याशी श्रीपाल राणा के सामने साख बचाना चुनौती रहेगी।

बीते चुनावों पर नजर डालें तो वर्ष 1967 के लोकसभा चुनाव में गयूर अली खान और 1971 में कांग्रेस के टिकट पर शफाकत अली चुनाव जीते थे। 1980 के चुनाव में चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी जनता पार्टी (एस) के टिकट पर सांसद चुनी गईं। 1984 में कांग्रेस के चौधरी अख्तर हसन जीते। वर्ष 1989 के बाद कांग्रेस हाशिए पर पहुंचती गई। नब्बे के दशक में उठी राम लहर ने भाजपा को संजीवनी दी। 1991 और 1996 में भाजपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह दूसरे नंबर पर थे, लेकिन 1998 में पार्टी के वीरेंद्र वर्मा ने सीट जीत ली। 1996 के लोकसभा चुनाव में सपा को अख्तर हसन के बेटे मुनव्वर हसन ने पहली जीत दिलाई। 98 में भाजपा को जीत मिली लेकिन अगले दो चुनाव रालोद के खाते में गए। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) और भाजपा ने तीन-तीन बार कैराना पर जीत दर्ज की है। सपा और बसपा सिर्फ एक बार जीते हैं। 2009 में कैराना जीतने का बसपा सुप्रीमो मायावती का अधूरा सपना पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की पत्नी तवम्सुम हसन ने पूरा किया। वर्ष 1984 में कैराना लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव में उतरने वाली मायावती को कांग्रेस की लहर में तीसरे पायदान पर ही संतोष करना पड़ा था।

राजनीतिक रूप से कैराना हसन परिवार और बाबू हुकुम सिंह के परिवार का गढ़ रहा है। कैराना के राजनीतिक माहौल को वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे में बदल दिया। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की लहर चली और 2014 में भाजपा के हुकुम सिंह 2.36 लाख वोटों से चुनाव जीते, जो अब तक का यहां का सबसे बड़ा अंतर है। वर्ष 2015 में कैरना के तत्कालीन सांसद बाबू हुकुम सिंह ने अपराधीकरण की वजह से शामली से व्यवसायियों के पलायन का मुझ उठाया था, जिस पर सियासत खूब गरमाई थी।

कैराना लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। आगामी 19 अप्रैल को इस सीट पर मतदान होगा। जिसकी तैयारी में सभी दलों के पदाधिकारी भी लगे हुए हैं। 2024 का रण अनौपचारिक तौर पर सज चुका है। एक तरफ सपा-कांग्रेस का गठबंधन है तो दूसरी तरफ भाजपा-रालोद एक साथ हैं। पिछला चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ने वाली बसपा अबकी बार एकला चलो की राह पर है। सपा ने तबस्सुम हसन की बेटी इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया है। उनके भाई नाहिद हसन सपा के टिकट पर कैराना से विधायक हैं। लोकसभा क्षेत्र की बाकी चार विधानसभा सीटों में 2 भाजपा और 2 रालोद के पास है।

भाजपा ने इस सीट पर दोबारा से सांसद प्रदीप चौधरी को जहां चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं सपा-कांग्रेस गठबंधन से हसन परिवार की बेटी इकरा हसन चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है। इसी तरह बसपा ने सहारनपुर के जिले के भावसी निवासी रिटायर्ड बीएसएफ के जवान श्रीपाल राणा को प्रत्याशी बनाया है। प्रदीप चौधरी के सामने दोबारा से इस बार भी सीट पर कमल खिलाने की चुनौती है। क्योंकि सीट पर दो बार सिर्फ जनता दल के प्रत्याशी हरपाल पंवार वर्ष 1989 और 1991 में सांसद रहे थे। इसके बाद कोई भी प्रत्याशी इस सीट पर दो बार लगातार जीत दर्ज नहीं कर सका।

प्रदीप चौधरी यदि इस बार चुनाव जीतते हैं तो जनता दल के लगातार दो बार सांसद बनने के रिकार्ड की बराबरी कर लेंगे। प्रदीप चौधरी के पिता मास्टर कंवरपाल सिंह भी तीन बार नकुड़ विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। प्रदीप चौधरी खुद तीन बार विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में प्रदीप चौधरी ने सपा की तबस्सुम बेगम को हराया था। प्रदीप चौधरी को 566961 वोट मिले थे जबकि तबस्सुम को 474801 वोट मिले थे। जबकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस के हरेंद्र मलिक रहे थे, जिन्होंने 69355 मत हासिल किए थे। हसन परिवार की बेटी इकरा हसन के सामने विरासत बचाने की चुनौती रहेगी। भाजपा के सांसद हुकुम सिंह की मौत के बाद वर्ष 2018 में उपचुनाव हुआ, जिसमें हसन परिवार की इकरा की मां तबस्सुम हसन ने रालोद से चुनाव लड़ते हुए 4,81,182 प्राप्त कर विजय हासिल की थी।

इससे पूर्व 2009 में भी तबस्सुम हसन ने बसपा से चुनाव लड़ा था और 2832590 मत हासिल कर जीत दर्ज की थी। 1996 में सपा से तबस्सुम हसन के पति मुनव्वर हसन ने चुनाव लड़ा था, उन्होंने 184636 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की थी। इससे पूर्व वर्ष 1984 में मुनव्वर हसन के पिता चौधरी अख्तर हसन ने कांग्रेस से चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज की थी। इकरा के भाई नाहिद हसन वर्तमान में कैराना से विधायक हैं। उधर, बसपा ने लोकसभा सीट पर सहारनपुर जिले के भावसी निवासी रिटायर्ड बीएसएफ के जवान श्रीपाल राणा को प्रत्याशी बनाया है। श्रीपाल राणा ने छह माह पूर्व ही बसपा ज्वाइन की थी। श्रीपाल राणा के सामने बसपा की साख बचाना चुनौती रहेगा। अब देखना यह है कि प्रदीप चौधरी इस सीट पर फिर से कमल खिलाने में कामयाब होते हैं या फिर बसपा या सपा चुनाव परिणाम को पलटती है। मतगणना के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा।

बसपा ने इस बार कैराना लोकसभा सीट पर श्रीपाल राणा को उतारकर ठाकुर-दलित कार्ड खेला है। इस स्थिति में बसपा को ठाकुर के साथ दलित, मुस्लिम और अन्य वर्गों का वोट मिलता है तो भाजपा और सपा का खेल भी बिगड़ सकता है। अन्य निर्दलीय और पार्टियों के प्रत्याशी भी भाजपा, सपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। कैराना लोकसभा सीट में पांच विधानसभ शामली, कैराना, थानाभवन, नकुड़ और गंगोह शामिल हैं। इस सीट पर मतदाताओं की संख्या-17 लाख 19 हजार 11 वोट है। कैराना लोकसभा सीट मुस्लिम वोटों का बड़ा गढ़ है. यहां पर करीब 17 लाख मतदाताओं में सर्वाधिक छह लाख मुस्लिम है। एक अनुमान के मुताबिक, 1.50 लाख जाट, 2.50 लाख दलित, 1.30 लाख गुर्जर, 1.35 लाख सैनी, 1.25 लाख कश्यप, 50 हजार ठाकुर व 60 हजार से ज्यादा वैश्य वोट है।

सुप्रीम कोर्ट ने मई 2012 में कारों के टिंटेड ग्लास (Black Glass) को लेकर निर्णय सुनाया था

कार के शीशे काले करने हैं तो जान लें ये नियम, फिर पुलिस नहीं काटेगी चालान!

परिवहन विशेष न्यूज

कार ग्लास फिल्म: कार के शीशे ब्लैक करने को काफी लोग स्वैग मानते हैं. इसीलिए, वह शीशों पर ब्लैक फिल्म चढ़वा लेते हैं लेकिन ऐसा करना गैर-कानूनी है. यातायात नियमों के अनुसार, कार के शीशों पर जीरो विजिबिलिटी वाली ब्लैक फिल्म लगवाने पर चालान है.

कार ग्लास फिल्म के लिए नियम: कार के शीशे ब्लैक करने को काफी लोग स्वैग मानते हैं. इसीलिए, वह शीशों पर ब्लैक फिल्म चढ़वा लेते हैं लेकिन ऐसा करना गैर-कानूनी है. यातायात नियमों के अनुसार, कार के शीशों पर जीरो विजिबिलिटी वाली ब्लैक फिल्म लगवाने पर चालान है. यह यातायात नियमों के उल्लंघन के दायरे में आता है. लेकिन, अगर इसके बाद भी आप कार के शीशे ब्लैक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी नियम है. निमयों का पालन करते हुए शीशे ब्लैक किए जा सकते हैं. दरअसल, नियम यह कहता है कि कार के शीशों को पूरी तरह से ब्लैक नहीं करना है. हालांकि, कुछ हद तक इन्हें ब्लैक किया जा सकता है. चलिए, आपको इसके बारे में बताते हैं.

ब्लैक फिल्म को लेकर क्या है नियम?

सुप्रीम कोर्ट ने मई 2012 में कारों के टिंटेड ग्लास (Black Glass) को लेकर निर्णय सुनाया था. कोर्ट ने निर्णय के अनुसार, कारों के आगे और पीछे के शीशे की विजिबिलिटी कम से कम 70 फीसदी होनी चाहिए. इसका मतलब है कि कार के आगे और पीछे वाले शीशे से कम से कम 70 फीसदी लाइट अंदर आनी चाहिए. वहीं, साइड ग्लास की विजिबिलिटी कम से कम 50 फीसदी होनी चाहिए. इसका मतलब भी यही है कि कार के साइड वाली शीशों से 50 प्रतिशत लाइट अंदर आनी चाहिए.

कितनी विजिबिलिटी वाली ब्लैक फिल्म लगवा सकते हैं?

अब अगर ऐसा नहीं होता है तो यातायात पुलिस चालान काट सकती है. इसीलिए, अगर आपका मन है कि आप अपनी कार के शीशे ब्लैक कराएं तो आपको यह बातें ध्यान में रखनी होंगी. नियम के अनुसार, आप कार के साइड वाले शोशों पर 50 प्रतिशत विजिबिलिटी वाली ब्लैक फिल्म लगवा सकते हैं और फ्रंट तथा रियर ग्लास पर 70 फीसदी विजिबिलिटी वाली ब्लैक फिल्म लगवा सकते हैं.

देवेंद्र सिंह (रचना यूनिवर्सिटी)

सरल कथन

1. आदेश के मुताबिक वाहन के किसी भी शीशे पर फिल्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा

2. नियम के अनुसार, आगे और पीछे के शीशों में 70% दृश्यता हो सकती है

3. साइड ग्लास में 50% हो सकता है

यह आदेश पारदर्शी फिल्म की भी अनुमति नहीं देता है, यही कारण है कि ओईएम ने सभी फिल्में वापस ले ली हैं

मैंने बहुत पहले कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ इस पर चर्चा की थी, 3एम में पारदर्शी फिल्म है जो यूवी किरणों को काटती है

इस आदेश के बाद मेश ब्लाइंड्स की शुरुआत हुई।

...जब बिना ड्राइवर दौड़ गई बोलेरो! ऑटोनोमस कार देख Anand Mahindra भी रह गए दंग,

भोपाल के एक स्टार्टअप ने अपने नए आविष्कार से सभी को हैरान कर दिया है। यहां तक कि Mahindra Mahindra के चेयरमैन Anand Mahindra भी इस प्रयोग से काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने स्टार्टअप की एक बोलेरो एसयूवी का वीडियो साझा किया है जो सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक से लैस है।

नईदिल्ली। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री नित नए प्रयोग कर रही है और समय के साथ एडवांस होती जा रही है। एडास और ऑटोनोमस सिस्टम जैसे फीचर्स एक समय में किसी से चमत्कार के कम नहीं थे और अब वह दिन दूर नहीं है जब सड़कों पर बिना ड्राइवर के गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी।

बिना ड्राइवर दौड़ गई बोलेरो

हाल ही में भोपाल के एक स्टार्टअप ने अपने नए आविष्कार से सभी को हैरान कर दिया है। यहां तक कि Mahindra & Mahindra के चेयरमैन Anand Mahindra भी इस प्रयोग से काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने स्टार्टअप की एक बोलेरो एसयूवी का वीडियो साझा किया है, जो सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक से लैस है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एसयूवी बिना किसी ड्राइवर के व्यस्त सड़कों पर आसानी से चल रही है।

किसने बनाई ऑटोनोमस कार?

इस एसयूवी को आईआईटी से ग्रेजुएट संजीव शर्मा द्वारा अपडेट किया गया है। उन्हें काफी दिनों से ऑटोनोमस तकनीक में रुचि है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बोलेरो एसयूवी ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से लैस दिखाई देती है।

इस तकनीक पर करती है काम

संभावित रूप से इसमें LiDAR सेंसर, कैमरे और रडार सिस्टम का उपयोग किया गया है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी है। एक्टिव सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए मशहूर Anand Mahindra ने अपने X हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए इसे सराहा है।

लेक्सस ने लॉन्च की नई NX 350h ओवरट्रेल लग्जरी SUV, जानें कैसे हैं फीचर्स और कीमत

लग्जरी कार और एसयूवी बनाने वाली कंपनी Lexus की ओर से भारतीय बाजार में नई SUV NX 350h Overtrail को लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी की ओर से नई अर्बन एसयूवी में किस तरह के फीचर्स को दिया गया है। कितना दमदार इंजन NX 350h Overtrail एसयूवी में मिलता है। इसकी क्या कीमत रखी गई है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में कम कीमत वाली कारों और एसयूवी के साथ ही महंगी और ज्यादा फीचर्स वाली लग्जरी SUV को भी काफी पसंद किया जाता है। Lexus की ओर से नई Urban SUV NX 350h Overtrail को लॉन्च कर दिया गया है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि कंपनी की ओर से इस एसयूवी में किस तरह के फीचर्स को दिया गया है। साथ ही इसे किस कीमत पर खरीदा जा सकता है।

Lexus ने लॉन्च की NX 350h Overtrail SUV

लेक्सस इंडिया ने भारतीय बाजार में नई अर्बन एसयूवी NX 350h Overtrail को लॉन्च कर दिया है। इस नई लग्जरी एसयूवी में कंपनी की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स और तकनीक को दिया गया है। कंपनी ने इस एसयूवी को खासतौर पर लाइफस्टाइल और ड्राइविंग अनुभव को ध्यान में रखते हुए बनाया है। भारतीय ग्राहकों को इस एसयूवी से दमदार प्रदर्शन के साथ ही कम्फर्ट भी मिलेगा।

कैसे हैं फीचर्स

लेक्सस की नई एसयूवी NX 350h Overtrail के बाहरी डिज़ाइन को टोन्ड लुक देने के लिए काले रंग का उपयोग किया गया है। इसमें ब्राइट ब्लैक स्पिंडल ग्रिल, ब्लैक डोर मिरर, ब्लैक डोर फ्रेम और ब्लैक डोर बेल्ट मोल्डिंग के साथ-साथ ब्लैक रूफ रेल्स और ब्लैक आउटसाइड डोर हैंडल को शामिल किया गया है। एसयूवी में स्पेशल हायर प्रोफाइल टायर के साथ मैट ब्लैक व्हील्स को दिया गया है। वहीं इसके इंटीरियर में भी लग्जरी का खासतौर पर ध्यान रखा गया है। इंजन स्टार्ट/स्टॉप, रिमोट एसी, रिमोट पावर विंडो, पैनोरमिक यूवी और आईआर कट रूफ, ड्यूल टोन इंटीरियर, स्टेयरिंग माउंटिड कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मेमोरी सीट्स जैसे कई फीचर्स को दिया गया है।

कितना दमदार इंजन

नई लेक्सस एनएक्स 350एच ओवरट्रेल में बड़ी क्षमता वाले हाइब्रिड सिस्टम को दिया गया है। इसमें 2.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इन-लाइन 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 179 किलोवाट का संयुक्त पावर आउटपुट पैदा करता है। इसके साथ ही इसमें बेहतर एवरेज के लिए लिथियम-आयन बैटरी और रिवाइज्ड ड्राइव फोर्स के साथ हाइब्रिड सिस्टम को जोड़ती है।

BMW i5 M60 xDrive की प्री-बुकिंग शुरू, चुनिंदा ग्राहकों को ही मिलेगी ये प्रीमियम सेडान

परिवहन विशेष न्यूज

BMW India ने अपनी आगामी ऑल-इलेक्ट्रिक सेडान i5 M60 xDrive के लिए प्री-बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। BMW i5 M60 xDrive में 600 bhp का जबरदस्त पावर आउटपुट और 820 Nm का टॉर्क है। ये इलेक्ट्रिक कार केवल 3.8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है जो इसकी परफॉरमेंस और स्पीड को दर्शाता है।

नई दिल्ली। BMW India ने अपनी आगामी ऑल-इलेक्ट्रिक सेडान, i5 M60 xDrive के लिए प्री-बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। इसे आने वाले महीनों में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी की ये प्रीमियम सेडान कंप्लीटली बिल्ट-अप (सीबीयू) रूट के माध्यम से भारत आएगी। इसे लिमिटेड कस्टमर को ही बेचा जाएगा, जिसकी डिलीवरी पूरे देश में मई 2024 में शुरू होने वाली है।

BMW i5 M60 xDrive की बैटरी, मोटर और रेंज

BMW i5 M60 xDrive में 600 bhp का जबरदस्त पावर आउटपुट और 820 Nm का टॉर्क है। ये केवल 3.8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, जो इसकी परफॉरमेंस और स्पीड को दर्शाता है। ये इलेक्ट्रि कार हाई कैपेसिटी बैटरी से लैस है, जो WLTP साइकिल के अनुसार एक बार चार्ज करने पर 516 किमी तक की ड्राइविंग रेंज प्रदान करता है।

कंपनी के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट

BMW i5 M60 xDrive से कंपनी को बड़ी उम्मीदे हैं। आपको बता दें कि कंपनी इंडियन मार्केट में बीएमडब्ल्यू आई7, बीएमडब्ल्यू आईएक्स, बीएमडब्ल्यू आई4, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 और मिनी एसई जैसे मॉडल बेचती है। उम्मीद है कि i5 M60 xDrive की शुरूआत से भारतीय इलेक्ट्रिक लग्जरी कार बाजार में बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया की स्थिति और मजबूत होगी।

अब दूर नहीं भारत में टेस्ला की एंट्री! शुरू किया Right Hand Drive कारों का उत्पादन

परिवहन विशेष न्यूज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की Electric Car बनाने कंपनी Tesla भारत में जल्द एंट्री कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी मिली है कि Tesla ने खास तौर पर इंडिया में कारों की बिक्री करने के लिए राइट हैंड ड्राइव (Right Hand Drive) कारों का उत्पादन शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में और क्या जानकारी मिली है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी Electric Car निर्माता Tesla जल्द ही भारत में अपनी कारों को ला सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने खासतौर पर भारत के लिए अपनी कुछ कारों का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में और क्या जानकारी मिली है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Tesla ने शुरू किया उत्पादन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला काफी जल्द ही भारत में अपनी कारों की बिक्री शुरू कर सकती है। कंपनी ने भारत के लिए खास तौर पर राइट हैंड ड्राइव कारों का उत्पादन शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इन कारों को जर्मनी बर्लिन में Tesla के प्लांट में बनाया जा रहा है। हालांकि कंपनी की ओर से इस बारे में किसी तरह की जानकारी को नहीं दिया गया है।

कब तक शुरू हो सकती है बिक्री

एक रिपोर्ट में एक व्यक्ति का हवाला दिया गया है। जिसके मुताबिक कंपनी ने बर्लिन में कारों का उत्पादन शुरू किया है। इस प्लांट में बनने वाली राइट हैंड ड्राइव कारों को भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है। व्यक्ति के मुताबिक Tesla की इन कारों को साल 2024 के आखिर तक भारत में लाया जा सकता है।

किन कारों को भारत लाया जाएगा

रिपोर्ट के मुताबिक जिस व्यक्ति की ओर से यह जानकारी दी गई है कि बर्लिन में बनीं राइट हैंड ड्राइव कारों को भारत लाया जाएगा। उसके मुताबिक पहले कुछ कारों का भारत में अलग अलग परिस्थितयों में टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अभी कंपनी के कौन से मॉडल्स को भारत लाया जाएगा, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। उम्मीद की जा रही है कि Tesla की ओर से Model 3 और Model Y को पहले भारत लाया जा सकता है।

भारत आएगी Tesla की टीम

हाल में ही इस बात की जानकारी भी मिली थी कि Tesla की एक टीम भारत का जल्द दौरा कर सकती है। अपने दौरे में यह टीम कंपनी के प्लांट के लिए जमीन की तलाश करेगी।

प्रदेश में भी बने भारत मंडपम

अनुज आचार्य

नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम, आर्कोप एसोसिएट्स और एडास सिंगापुर द्वारा पुनः डिजाइन किया गया एक प्रतिष्ठित भवन है जो देश की वास्तुकला को परिभाषित करता है और उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति और ज्ञान केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करता है।

हिमाचल सरकार शिमला में हिमाचल हाट बनाने जा रही है। हिमाचल हाट बनने से शिमला में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को प्रदेश के हर जिला का पारंपरिक भोजन हर समय उपलब्ध रहेगा और वह कभी भी इसका आनंद ले पाएंगे। इसी प्रकार हर जिला मुख्यालय पर जगह उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वह अपने उत्पादों की वहां बिक्री कर आत्मनिर्भर बन सकें'

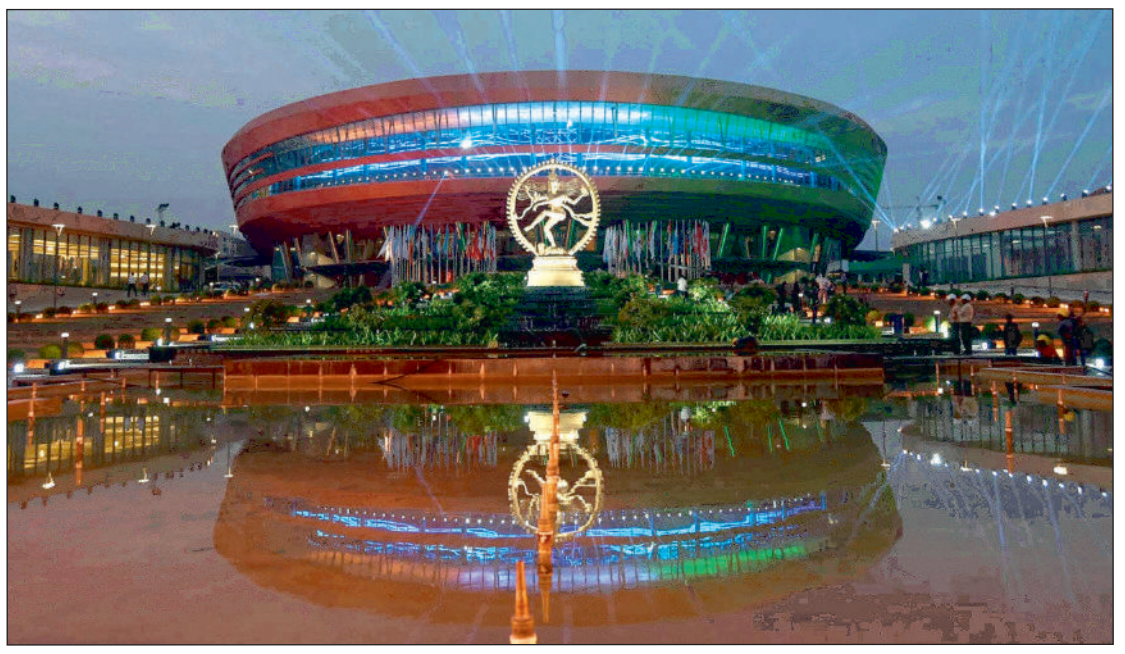

लगभग 150 एकड़ क्षेत्र में निर्मित प्रगति मैदान भारत के सबसे बड़े प्रदर्शनी केंद्रों में से एक है और दिल्ली में प्रदर्शनियों और सम्मेलनों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। भारत ने जी-20 के आयोजन के दृष्टिगत वास्तुशिल्प की अनूठी उपलब्धि को जोड़ते हुए प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एक नए कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का निर्माण करवाया है जो आधुनिकता का परिचायक भी है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम, आर्कोप एसोसिएट्स और एडास सिंगापुर द्वारा पुनः डिजाइन किया गया एक प्रतिष्ठित भवन है जो देश की वास्तुकला को परिभाषित करता है और उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति और ज्ञान केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। यहां बड़े प्रदर्शनी स्थल और सहायक बुनियादी ढांचे के साथ 4800 यात्री कार इकाइयों (पीसीयू) की पार्किंग सहित अन्य संबंधित सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इसी के साथ इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) एक अत्याधुनिक, विश्वस्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर बनाने की दृष्टि से भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना है जो आकार और गुणवत्ता में, अंतरराष्ट्रीय और साथ ही राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और व्यापार शो के लिए एक कुशल और गुणवत्तापूर्ण आयोजन स्थल की पेशकश करता है।

25703 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से यह परियोजना सेक्टर-25, द्वारका में विकसित की जा रही है और इसे लगभग 303000 वर्ग मीटर के साथ केंद्रीय व्यापार जिले (सीबीडी) के पैमाने पर बनाने की कल्पना की गई है। प्रदर्शनी स्थल का क्षेत्रफल 60000 वर्ग मीटर है, जबकि सम्मेलन क्षेत्र का क्षेत्रफल 50000 वर्ग मीटर है। यहां बहुउद्देश्यीय क्षेत्र के साथ-साथ खुदरा, वाणिज्यिक कार्यालयों, आतिथ्य उपयोगकर्ताओं के लिए मनोरंजन और जीवन शैली को दर्शाने वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त स्थान है। यह सुविधा देश में अपनी तरह की पहली होगी जिसमें प्रदर्शनी हॉल में बड़े कॉलम मुक्त स्थान होंगे और बड़े पैमाने पर रक्षा और एयरोस्पेस प्रदर्शनियों की मेजबानी करने की क्षमता होगी। कन्वेंशन सेंटर परिसर में 11000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता होगी और 6000 लोगों की क्षमता वाला एक विश्वस्तरीय हॉल होगा। आज आवश्यकता है कि केंद्र सरकार छोटे स्तर पर पर ही सही, भारत मंडपम की तर्ज पर प्रत्येक राज्य के दो-तीन महत्वपूर्ण शहरों में आधुनिक एवं सुविधाओं से परिपूर्ण प्रदर्शनी स्थलों का निर्माण करवाए, ताकि नई दिल्ली में आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों की तरह के आयोजनों को राज्यों के नागरिक भी निकटता से देख सकें। पिछले दिनों 7 मार्च से 11 मार्च 2024 तक भारत की एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी 'आहार मेले' का आयोजन प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया। आहार खाद्य और आतिथ्य में एशिया का सबसे प्रसिद्ध ब्रांड है। मैं स्वयं इस प्रदर्शनी को देखने के लिए दिल्ली में मौजूद था।

हर वर्ष की तरह इस मेले में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इस आहार मेले में देश-विदेश के 1800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। आहार प्रदर्शनी में रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर बिजनेस की कई महत्वपूर्ण जानकारियां वहां आने वाले लोगों को मिलीं। अलग तरह के चॉकलेट बॉक्सेस से लेकर घर के पर्दे, किचन हैक्स का सामान और विदेशी खानपान भी चखने को मिले। पिज्जा, चाइनीज ड्राइफ्रूट्स, डिजाइनर क्रॉकरी और फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाने वाली अत्याधुनिक मशीनों का भी वहां प्रदर्शित किया गया। कई स्टॉलों में लोगों को कई स्वादिष्ट डिश भी चखने को दी गईं। जिन लोगों को ऐसे इवेंट्स में जाना पसंद हो और समयाभाव के कारण बड़े शहरों का रुख नहीं कर पाते हैं, उनकी सुविधा के लिए छोटे राज्यों में भी प्रगति मैदान की तर्ज पर कम से कम 2-3 हॉल वाले प्रदर्शनी स्थलों का निर्माण आज के दौर की मांग है और वैसे भी दिल्ली जैसे बड़े एवं महंगे महानगर में रहना आम आदमी के बलबूते से बाहर की बात है। यह सर्वविदित है कि सूरजकुंड और दिल्ली हाट जैसे मेला आयोजन स्थलों में भी लाखों की संख्या में लोगों की भागीदारी रहती है। दो वर्ष पूर्व मंडी में एफएसएसएआई द्वारा एक दिवसीय 'ईट राइट' मेले का आयोजन इंदिरा मार्केट की खुली छत पर किया गया था। जाहिर है कि हिमाचल के नित बदलते मौसम के दृष्टिगत खुली जगहों में ऐसे आयोजन में भाग लेने वाले व्यापारियों के साथ-साथ दर्शकों को भी असुविधा होती है। इस मेले में मंडी जिला के विभिन्न स्थानों से आए महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों ने लोकल खाद्य उत्पादों के स्टॉल लगाए थे और इसके साथ ही विभागीय प्रदर्शनियों को भी लोगों की जानकारी के लिए लगाया गया। इनके जरिए लोगों को अच्छे भोजन के बारे में जागरूक और पौष्टिक भोजन की आदत बारे प्रेरित किया गया। हिमाचल सरकार शिमला में हिमाचल हाट बनाने जा रही है। हिमाचल हाट बनने से शिमला में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को प्रदेश के हर जिला का पारंपरिक भोजन हर समय उपलब्ध रहेगा और वह कभी भी इसका आनंद ले पाएंगे। इसी प्रकार हर जिला मुख्यालय पर जगह उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वह अपने उत्पादों की वहां बिक्री कर आत्मनिर्भर बन सकें।

इसके अतिरिक्त हिमाचली धाम और अन्य पारंपरिक व्यंजनों के पेटेंट के संबंध में भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वर्तमान दौर में अब भारतीय बड़ी संख्या में भारत के अन्य राज्यों में पर्यटन हेतु आ-जा रहे हैं और विदेशी भी भारत घूमने आ रहे हैं, लिहाजा ऐसे भव्य मंडपों का निर्माण और एक छत के ही नीचे सभी जानकारियों का प्रदर्शन न केवल राज्यों की प्राचीन संस्कृति, इतिहास एवं शिल्पकला आदि को रेखांकित करेगा, अपितु स्थानीय लोगों को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे बदलावों से अवश्य ही अवगत और अद्यतन रखेगा।

संपादक की कलम से

कुछ जलवे, कुछ शिकार

हिमाचल में लोकसभा चुनाव के साथ नत्थी विधानसभा उपचुनाव की तासीर में या तो जलवे करेंगे कमाल या अति महत्त्वाकांक्षा हो जाएगी शिकार। पहले जलवों का जिक्र करें, तो भाजपा की रणनीति में केंद्रीय ताकत का एहसास, आत्मविश्वास और अपनी संगठनात्मक मशीनरी का प्रदर्शन है। पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे संगठन के साथ साज बजा रही है। उसके अधिकांश उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस से आए पूर्व विधायक अपने साथ जो सामान लाए हैं, उसका प्रदर्शन परिचय दे रहा है। धर्मशाला में सुधीर शर्मा का परिचय सम्मेलन अपनी धाक में कांग्रेस की खोपड़ी में प्रश्न पैदा जरूर कर रहा है, क्योंकि पार्टी की हर तह में अब कोई न कोई उम्मीदवार टर्रा रहा है। सदमें में भाजपा के भी कई तीर हैं, लेकिन चुनावी योजना में यह पार्टी जलवों का श्रृंगार करने में माहिर है। हम इसी आधार पर राजेंद्र राणा के मार्फत सुजानपुर के दुर्ग में हलचल देख सकते हैं। यह दीगर है कि भाजपा के कई गवाह अब कांग्रेस में गोटियां फिट कर रहे, तो यह भी देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में कौन अपने जलवे का हल जोत रहा है। बहरहाल जलवे से उम्मीदवारों का चयन संभव है, तो मंडी से भाजपा की उम्मीदवार कंगना रनौत में यह खासियत राष्ट्रीय चर्चा का विषय है। उम्मीदवार घोषित होने से पहले ही कंगना के बयान-कंगना के विवाद, इतने अधीर तो रहे ही हैं कि भाजपा के नाम पर कहीं भी पत्थरबाजी हो जाए। शायद इसलिए बयानों-विवादों का एक मुकाबला उनके और सुक्खू सरकार के लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बीच शुरू हो चुका है। जलवा इसी लोकसभा क्षेत्र में वीरभद्र सिंह के परिवार का भी रहा है, लेकिन अब यहां धीरे-धीरे कंगना बनाम प्रतिभा सिंह के बीच पार्टियों के संघर्ष से कहीं अधिक दोनों नेत्रियों के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आकर टिकेगा, तो सारी परिपार्टियां फिर से लिखी जाएंगी। कंगना का बड़बोलापन और हाजिरजवाबी पर मतदाता फिदा होता है या वीरभद्र सिंह के परिवार की गरिमा चुनाव के सिर पर सवार रहती है, यह देखना रोचक होगा।

कांगड़ा से लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले, लेकिन भाजपा की ओर से डा. राजीव भारद्वाज की पेशकश में वयोवृद्ध नेता शांता कुमार का जलवा जरूर देखा जा रहा है। यह दीगर है कि अब तक जलवा दिखा चुके त्रिलोक कपूर की दावेदारी पर विराम लगाकर, उनके सदा नजदीक रहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा नए अवतरण में हैं। प्रदेश के सामथ्र्य में राजनीतिक जलवे का स्वाभाविक पुरुषार्थ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आशावान है और अगर वह इन चुनावों में पचास फीसदी भी सफलता हासिल कर पाते हैं, तो कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति में भविष्य की अगवाई करते हुए देखे जाएंगे। इन चुनावों में हिमाचल के असली शिकारी का भी पता चलेगा। विधायकों के इस्तीफों के माध्यम से कौन किसका शिकार कर गया, इसका पता भी चुनाव की सारी कसरतें बताएंगी। शिकार की टोह में हिमाचल की राजनीति आज भी जहां खड़ी है, वहां कई चाबुक व तलवार लटके हैं। बात सिर्फ सरकार को वापस पटरी पर लाने की नहीं, बल्कि ऐसी किलेबंदी की जरूरत है जो आगे चलकर समूची राजनीति को सबक हो सकती है। ऐसे में हिमाचल के कुछ नेताओं को सूचीबद्ध करके हम या तो जलवा देख पाएंगे या उन्हें शिकार होते भी देख सकते हैं। जनता की निगाहों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कंगना रनौत, अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, राजेंद्र राणा व सुधीर शर्मा से जुड़े कई ऐसे विषय हैं, जो उनके जलवों की आशा रखते हैं, लेकिन ये चुनाव कातिल शिकारी के नाम कहीं अधिक दर्ज होंगे। यह पहला चुनाव है जहां विकास बनाम विकास पुरुषों की शिनाख्त होगी।

राय

ढाई आखर प्रेम का

हमारे संतों, ऋषियों, मुनियों, मनीषियों ने सीख दी है कि मनुष्यों से ही नहीं, सभी जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों तक से प्रेम करो। इस सृष्टि की हर वस्तु से प्रेम और पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ भक्ति, अध्यात्म की महत्वपूर्ण सीढियां हैं। गुरू नानक देव जी, संत कबीर, संत रविदास, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, योगी राज प्रभु राम लाल जी, गुरुदेव ओम स्वामी जी आदि की शिक्षाओं का सार भी यही है। ये सब दिव्य आत्माएं हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। यह एक कड़वा सच है कि बहुत बार अपने ज्ञान के अभिमान में विशेषज्ञों का नजरिया संकुचित हो जाता है और वे अपनी किताबी सीख से आगे नहीं जा पाते, और जीवन की कई सच्चाइयों को अस्वीकार करके उनसे अनभिज्ञ रह जाते हैं। विज्ञान की बात तो छोड़िए, विभिन्न धर्मों में भी गहरे मतभेद हैं। कोई धर्म जन्म-जन्मांतर की बात करता है तो कोई पुनर्जन्म को ही नहीं मानता। धर्म फिर एक शारीरिक चीज है, कर्मकांड है, अध्यात्म उससे कहीं आगे की बात है। यही कारण है कि ऋषियों मुनियों ने धर्म की नहीं बल्कि अध्यात्म की बात की है। पुनर्जन्म की ही बात करें तो बहुत से धर्म इस विचार को पूरी तरह से नकारते हैं, लेकिन सच यह भी है कि पुनर्जन्म के बहुत से साक्ष्य दुनिया भर में उपलब्ध हैं और उन पर कोई विवाद नहीं है।

यही हाल विज्ञान का भी है। यही कारण है कि एक सीमा के बाद विज्ञान आगे नहीं बढ़ पाता, तो फिर हमें अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। अध्यात्म बहुत सहज है, बहुत सरल है, उसे समझना भी कठिन नहीं है, परंतु आधुनिकता के चक्कर वाले व्यक्ति के लिए उसकी थाह पाना कठिन है। प्रतियोगिता के युग में जी रहा व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि पूजा सिर्फ तभी पूजा है जब हम प्रेममय हो जाते हैं, देश, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र की बात छोडक़र हर व्यक्ति से प्रेम करने लगते हैं, बिना कारण प्रेम करने लगते हैं, और व्यक्ति से ही नहीं, हर वस्तु से प्रेम करने लगते हैं, हर जड़-चेतन जीवन का सम्मान करने लगते हैं, बिना कारण, बिना लालच, बिना किसी डर के। यह जीवनशैली अपना लें तो मन हमेशा प्रसन्न-प्रफुल्लित रहता है। जब हम प्रेममय हो जाते हैं तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं, किसी बात का गिला नहीं रह जाता, क्रोध नहीं रह जाता, पछतावा नहीं रह जाता, इन सबकी जगह कृतज्ञता का भाव आ जाता है, समर्पण का भाव आ जाता है, सेवा का भाव आ जाता है। इस तरह हम अध्यात्म की कई सीढियां चढ़ जाते हैं। हम आध्यात्मिक होते हैं तो ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं। बस हमें यह समझना जरूरी है कि आध्यात्मिक होने के लिए, बोध पाने के लिए घर, निर्वाण के लिए या परमात्मा को पाने के लिए घर, परिवार, दुनिया छोड़ कर संत बन एकमात्र रास्ता नहीं है। यह कोई नहीं कहता कि संत बन जाना गलत है। यह कोई नहीं कहता कि कर्मकांड गलत है। यह कोई नहीं कहता कि दुनिया छोड़ कर हिमालय पर कठिन तपस्या करना गलत है। पर सच यही है कि बुद्ध हो जाने के बहुत से रास्तों में से यह भी एक रास्ता है। चूंकि बोधिसत्व प्राप्त करने के कई रास्ते हैं, इसलिए किसी अन्य मत की आलोचना नहीं होनी चाहिए। परमात्मा एक है, पर परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते कई हैं। 'सहज संन्यास मिशन' के अनुगामी के रूप में मेरा मानना है कि दुनिया माया नहीं है, जीवन सपना नहीं है। हम जीवित हैं, हमें एक शरीर मिला है और हम इस दुनिया में हैं, तो यह भी एक सच है, और इसे झुठलाया नहीं जाना चाहिए। दुनिया में रहकर दुनिया वालों से प्रेम करना, उनकी सेवा करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जीवन का पाठ यही है। सहज संन्यास के अनुयायियों की एक और मान्यता यह है कि हर व्यक्ति की स्थितियां अलग हैं, परवरिश अलग है, पालन-पोषण अलग है, परिवार अलग है, परिवार के विश्वास अलग हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि किसी एक स्थिति पर दो अलग व्यक्तियों की प्रतिक्रिया एक समान हो। अगर एक शेर किसी हिरण का पीछा कर रहा है तो सच्चाई यह है कि दोनों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। हिरण यदि शिकार हो जाएगा तो जान गंवा देगा, लेकिन यदि शेर, शिकार नहीं करेगा तो भूखों मर जाएगा।

छिलकों की छाबड़ी : नकली फानूस बनी दुनिया

समय इतना बदल गया है कि अब इसकी सही से पहचान भी नहीं हो पाती। पहले बड़ी उम्र का हो जाना वरिष्ठता होती थी। पूरा नगर, पूरा गांव बड़े-बूढ़ों का सम्मान करता। अब बूढ़ा हो जाने का अर्थ है, बासी हो जाना। पुराने चावलों की आज कद्र नहीं होती, उनके माथे पर 'बासी कढ़ी में उबाल आना' जैसे मुहावरे चिपका दिए जाते हैं। आपने दिन-रात मेहनत करके खुद चना-चबेना खाकर अपनी दिन-रात की मेहनत से अपने बेटों, भतीजों को पढ़ाया, रोजगार करने के काबिल बनाया, और आज वे आपको आंखें दिखाते हुए कहते हैं, 'यह आपका अपना चुनाव था, हम तो आपको कहने नहीं गए थे कि आप चना-चबेना खाकर अपने हक की रोटी खर्च हमें काबिल बनाओ।' यह आपका अपना खुद किया गया चुनाव था। इसके बल पर हमसे किसी राहत-रियायत की उम्मीद न करना। आपकी यह फरियाद हमें टसुवे बहाने जैसी लगती है। फिर किस हक की कमाई करने की बात आप कहते हैं। आजकल हक या बिना हक की कमाई होती कहां है? फिर यह नौजवानों का देश है। देश की आधी आबादी पैंतीस की उम्र से नीचे है, और उनमें से अधिकतर बेकार हैं। देश के आंकड़ा शास्त्री कहते हैं कि समय बीतने के साथ-साथ चिकित्सा विज्ञान की तरक्की के साथ इस देश के लोगों की औसत उम्र बढ़ती जा रही है, अर्थात हर साल पहले से अधिक बूढ़ों की संख्या लोगों को नासूर की तरह परेशान करती रहती है। आप हक की कमाई की बात कहते हैं? जनाब किसी भी तरह कमाई होनी चाहिए, चाहे किसी नाजायज रास्ते से ही हो जाए। आजकल तो चौराहे पर भीख भी दीनता और आहत होने का आडम्बर किए बिना नहीं मिलती। खैरात मांगने-कमाने का यह फार्मूला नीचे से ऊपर तक चलता है। जरूरतमंद और दीनविहीन होने की नौटंकी जितनी कामयाबी से करो, उतना ही सफलता आपका माथा चूमेगी। वैसे आजकल खैरात भी सरकारी मुहर के साथ पेशेवाराना हो गई। इस देश की भूख, बेकारी, बीमारी का एक ही समाधान है, खैरात। रोटियों के फ्री कैम्प से लेकर औषधियों और टीकों के फ्री कैम्प लगाओ, अपनी फोटो अखबार में छपवाओ। चेहरा यूं बहुचर्चित हो जाओ, तो उसे किसी चुनाव की ओलम्पिक में दौड़ाओ।

रोशन मीनारों की नींव में इन पथमसीहाओं का बलिदान नहीं, नित्य नए मुहावरे गढ़ कर एक नई क्रांति का आभास पैदा कर सकने की सामथ्र्य होती है, क्योंकि ऐसी कोई सामथ्र्य बूढ़ों के पास नहीं रहती। वह तो नैतिकता और आदर्शों की दुहाई देते नजर आते हैं। इसलिए उन्हें जितनी जल्दी, वे असम्बद्ध करार देकर नकार दिया जाए, उतना ही अच्छा। पिछले दिनों जब महामारी का प्रकोप अनियंत्रित हो रहा था, तो न्याय पीठ से भी एक वचन मुखरित हुआ, 'अरे औषधि कम है, टीके नहीं मिलते, तो पहले अपनी युवा शक्ति को इससे बचाओ। टीके लगाओ। बूढ़ों का क्या है?' जी हां, बूढ़े से अधिक अनचाहा बोझ और कोई नहीं। बूढ़ों की दुर्दशा पर सियासत करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन एक सेहतमंद बूढ़ा उन्हें दुःसंवाद नजर आता है। यह सुनी-सुनाई बात नहीं, अभी किए गए पेंशन के कानून के संशोधन ने भी हमें समझाया है। अभी खबर मिली है कि भौतिकता से ललचाये और बौराये रिश्तदार पेंशन पाते बूढ़ों को मौत के घाट उतारने लगे हैं, ताकि उनकी पारिवारिक पेंशन से अपनी जेबें भर सकें, रिश्तेदारी में इसे लेने का अपना हक जता मुकद्दमे बरसों चलते हैं। इस बीच उनकी संतान को कोई कष्ट न हो और पेंशन का भुगतान बिना विलम्ब होता रहे। सरकार ने कानून बनाया। इसलिए नाबालिग बच्चों के संरक्षक अधिकारी बनेंगे। अब स्वाभाविक संरक्षक कौन है? इस पर झगड़े बढ़ेंगे। नए वेतन आयोग ने पेंशन बढ़ा दी है, तो ऐसी निर्मम हत्याएं और सामने आएंगी। जा रे जमाना, युगधर्म ने कैसी चाल बदल ली?

सुरेश सेठ

विचार

वोट में तब्दील होने वाले मुद्दों की तलाश बड़ी चुनौती

एक बात और चुनाव घोषणा पत्रों में मुफ्त की सुविधाओं की भरमार भी अब लोगों को अधिक लुभाने वाली नहीं लगती। कारण साफ है इससे एक और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर देने वाला अपने को ठगा समझने लगा है, वहीं लाभार्थी इसे राजनीतिक दलों की कमजोरी समझने लगा है।

18 वीं लोकसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका हैं वहीं पहले चरण की 102 सीटों के लिए नामांकन का कार्य पूरा होने के साथ ही एनडीए ने 31 मार्च को मेरठ और इंडी गठबंधन ने नई दिल्ली से चुनावी केंपेन का आगाज कर दिया है। लोकसभा के सातों चरणों के मतदान तक राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव रैलियों, रोड़ शो सहित विभिन्न मंचों से एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। सौ टके का सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में चुनाव अभियान के दौरान आखिर मुख्य मुद्दे क्या बनेंगे ? हाल ही पांच विधान सभा चुनावों के दौरान गांरटियों की खूब चर्चाएं रही। एक तरफ गांरटियां थी तो दूसरी और बीजेपी ने मोदी को ही गारंटी बताकर प्रचारित किया। दरअसल देखा जाएं तो पिछले कुछ चुनावों से चाहे वे लोकसभा के हो या विधानसभाओं के चुनाव हो, सीधे जनता से जुड़े मुद्दें तो कहीं नेपथ्य में ही रह जाते हैं। तस्वीर का एक पक्ष यह भी है कि जनता से जुड़े मुद्दों को आमजनता भी अब मुद्दे या चुनावी एजेंडा नहीं मानने लगी है। इसका कारण भी कुछ और ही होता जा रहा है। किसी जमाने में गरीबी हटाओं या भ्रष्टाचार मिटाओं या महंगाई या बेरोजगारी तो सकारात्मक प्रचार अभियान में विकास की बात आदि मुद्दे महत्वपूर्ण होते थे पर अब देखा जाए तो यह मुद्दे वोट में तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। पिछले चुनावों के अनुभव हमारे सामने हैं। दर असल अब नकारात्मक प्रचार राजनीतिक दलों पर उलटा पड़ने लगा है। पिछले दो लोकसभा के चुनावों में चौकीदार, सेना के साक्ष्य, चाय वाला आदि ऐसे वक्तव्य रहे जिसका जितना अधिक उपयोग हुआ वह भाजपा और नरेन्द्र मोदी के पक्ष में ही गया। दरअसल अब वोट विश्वसनीयता यानी की भरोसे और वोल्डनेस पर पड़ने लगे हैं। एक बात यह भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आजादी के 75 साल बाद भी किसी दल का वोट प्रतिषत 50 प्रतिशत का आंकड़ा छू नहीं पाया है। दूसरी और चुनाव आयोग द्वारा लाख प्रयासों के बाद भी 100 में से 33 प्रतिशत मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर मतदान के लिए ले जाने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। खैर यह अलग विचारणीय मुद्दे हैं।

विपक्ष के प्रयास है कि सत्तारुढ़ द्वारा संबैधानिक संस्थाओं यथा ईडी, आईटी आदि जांच एजेंसियों का हथियार के रुप में उपयोग, चुनावी बॉण्ड, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि को प्रभावी तरीके से चुनावी मुद्दा बनाया जाये पर अभी तक जो दिखाई दे रहा है उसमें साफ है कि यह मतदाताओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे बन नहीं पा रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण तो विपक्षी खासतौर से इंडी के दलों का जुड़ना बिखरना जारी है। एक तरफ ममता पं.बगांल में कांग्रेस द्वारा वामपंथी दलों के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ने को खुले आम भाजपा को लाभ बताने वाला निर्णय बता रही हैं वहीं बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली में कांग्रेस का छोटे पार्टनर के रुप में सामने आने, पंजाब में आप से सीटों के बंटवारें को लेकर समझौता ही नहीं होने, बसपा का अलग रुख, अजित जनता दल का बीजेपी के साथ आना, ओडीसा में बीजद सहित विरोधाभास सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली की रैली से साफ हो जाता है कि विपक्ष का जो पैनापन होना चाहिए था वह लगभग असरदार नहीं दिखा। चुनावी बॉण्ड का मुद्दा जिस तरह से उछला वह अपनी धार नहीं दिखा पाया क्योंकि चुनावी चंदा सभी ने लिया चाहे वो कम हो या ज्यादा। दूसरी बात आमजन का यह सोच माना जा सकता है कि सभी राजनीतिक दल चुनावी चंदा लेते हैं और साफ है कि इसका फायदा सत्तारुढ़ दल को अधिक ही मिलता है। चंदा देने वाला अपने निहितार्थ देखता है और यही कारण है कि वह सत्तारुढ़ दल को अधिक चंदा देता है। इसलिए जिस तरह से यह बड़ा मुद्दा बनने की संभावना देखी जा रही थी वह कहीं पीछे ही रह गई। इसी तरह से केजरीवाल सहित आप नेताओं पर ईडी छापों और जेल का मुद्दा भी अधिक असर दिखाता नहीं लग रहा। इसका कारण भी साफ है कि केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही सत्ता में आये थे पहलीबात तो उनके नेताओं पर शराब ठेकों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, दूसरी और बार बार सम्मन आने पर भी रेस्पांस नहीं करने और गिरफ्तारी के बाद भी पद पर बने रहने का आमजन में अभी तो नकारात्मक असर ही दिखाई दे रहा है। इस मामलें में लोग लालू की बड़ाई करने लगे हैं कि लालू ने गिरफ्तार होते ही अपना पद त्याग दिया और भले ही राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया पर पद की गरिमा को तो बनाये रखा। केजरीवाल द्वारा बार बार सम्मन की अवहेलना करने और त्यागपत्र नहीं देने से लोगों में केजरीवाल के पदलोलुपता का संदेश गया अन्यथा निश्चित रुप से केजरीवाल के प्रति सहानुभूति होती और इसका लाभ समस्त विपक्ष को मिलता पर लगता है एक अच्छा अवसर खो दिया गया है। अब सवाल महंगाई को लेकर आता है तो महंगाई किसी जमाने में अपना असर दिखाती थी और प्याज के भाव बढ़ने के कारण सरकार को जाते हुए हमनें देखा है पर लगता है अब यह मुद्दा भी कुंद पड़ता जा रहा है। इसका कारण है बेरोजगारी और मंहगाई को जिस तरह से विपक्ष को चुनावी इशु बनाना चाहिए था उसमें वह सफल नहीं हो पा रही हैं।इस चुनाव में किसानों का मुद्दा तो अभी तक दिखाई ही नहीं दे रहा।

इसे भी पढ़ें: बिहार की राजनीति का 'चिराग' संभावना का वाहक

एक बात और चुनाव घोषणा पत्रों में मुफ्त की सुविधाओं की भरमार भी अब लोगों को अधिक लुभाने वाली नहीं लगती। कारण साफ है इससे एक और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर देने वाला अपने को ठगा समझने लगा है, वहीं लाभार्थी इसे राजनीतिक दलों की कमजोरी समझने लगा है। चुनावी बॉण्ड भी इसलिए अधिक बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा कि कमोबेस सभी दलों को चंदा मिला है। किसी ने भी इस तरह से चंदा लेने से ना नहीं किया। दूसरी और जहां तक आमआदमी का प्रश्न है वह जानता है कि चुनावी चंदा देने वाले पैसे वाले प्रभावशील लोग हैं। आमआदमी तो इतना चंदा देने से रहा। यह भी जानते हैं कि चुनावों के लिए चंदा लिया ही जाता है। दूसरी और मजे की बात यह है कि चंदा पैसों वालों से लेने के बावजूद आममतदाताओं को साधनें में सत्तारुढ़ दल सफल रहा है। साफ है कि चंदा देने वालों के वोट गिनती के ही होते हैं।

साफ है कि 18 वीं लोकसभा के चुनाव प्रचार अभियान में संवैधानिक संस्थाओं के उपयोग, चुनाव बॉण्ड, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि मुद्दें अधिक चलने वाले नहीं हैं। राम मंदिर, धारा 370 या इसी तरह के अन्य मुद्दों को विपक्ष उठाता भी है तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा।

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

ट्रेन संचालन मानकों में संशोधन पर मंत्रालय ने मांगे विचार, संरक्षा आयुक्त ने उठाए थे सवाल

ट्रेन संचालन मानकों (Train Operation Norms) में हालिया संशोधनों पर रेलवे की विभिन्न जोनों से उनके विचार देने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा आमंत्रित किया गया है। दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद मुख्य रेलवे संरक्षा आयुक्त (CCRS) ने इन बदलावों को वापस लने का सुझाव दिया था। वर्ष 2023-24 में 31.10.2023 तक परिणामी दुर्घटनाओं की कुल संख्या 25 थी जो 2022-23 की इसी अवधि के समान है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। रेल मंत्रालय (Railway Ministry) ने ट्रेन संचालन मानकों (Train Operation Norms) में हालिया संशोधनों पर रेलवे की विभिन्न जोनों से उनके विचार आमंत्रित किए हैं। गंभीर दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद मुख्य रेलवे संरक्षा आयुक्त (CCRS) ने इन बदलावों को वापस लने का सुझाव दिया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय(Ministry of Civil Aviation) के तहत आने वाले सीसीआरएस का कहना है कि पिछले वर्ष एक अप्रैल से 31 अक्टूबर तक पांच गंभीर दुर्घटनाएं हुईं जबकि 2022-23 की इसी अवधि में ऐसी सिर्फ दो दुर्घटनाएं हुई थीं। इन संशोधनों से भविष्य में ट्रेन दुर्घटनाओं की संभावना में वृद्धि हो सकती है।

दरअसल, रेल मंत्रालय ने 2023 में 21 जुलाई और 25 जुलाई को ट्रेन यातायात संचालन के सामान्य नियमों में संशोधन किए थे और जोनल रेलवे को इसकी अनुमति प्रदान की थी कि स्टेशन यार्ड में गैर-पृथक लाइनों पर एक साथ ट्रेनों का संचालन किया जा सके।

एक रेलवे सुरक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि गैर-पृथक लाइनें बड़े यार्डों में ऐसी अतिरिक्त रेल लाइनें होती हैं जो बिना इंटरलॉकिंग या सिग्नलिंग प्रणाली के लगातार ट्रेन संचालन वाली लाइनों से स्थायी रूप से जुड़ी होती हैं। इन लाइनों का इस्तेमाल रेल इंजनों या डिब्बों की शंटिंग के लिए साइडिंग के रूप में किया जाता है। पहले दोनों लाइनों पर एकसाथ संचालन की अनुमति नहीं थी।

ट्रेन संचालन मानकों में बदलाव

एक रेलवे सुरक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि नॉन-आइसोलेटेड लाइनें बड़े यार्डों में वे अतिरिक्त रेल ट्रैक हैं जो बिना किसी इंटरलॉकिंग या सिग्नलिंग सिस्टम के स्थायी रूप से चलने वाली लाइनों से जुड़े होते हैं। इन लाइनों का उपयोग लोकोमोटिव या कोचों की शंटिंग के लिए साइडिंग के रूप में किया जाता है।

पिछले मानदंडों के अनुसार, यदि कोई ट्रेन रनिंग या मेन लाइन पर चलती है, तो गैर-पृथक लाइनों पर अन्य ट्रेनों को चलने की अनुमति नहीं थी। हालांकि, नए मानदंड ने इसे उलट दिया है और रनिंग के साथ-साथ गैर-पृथक लाइनों पर एक साथ संचालन की अनुमति दी है।

इन परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया देते हुए, सीसीआरएस ने पिछले साल 23 नवंबर को रेलवे बोर्ड को लिखा और इन संशोधनों को वापस लेने के सुझाव के साथ-साथ विभिन्न सुरक्षा चिंताओं को भी लाल झंडी दिखाई।

रेलवे सुरक्षा आयोग द्वारा दुर्घटनाओं के आंकडे

सीसीआरएस ने कहा कि वर्ष 2023-24 में 31.10.2023 तक परिणामी दुर्घटनाओं की कुल संख्या (25 संख्या) 2022-23 की इसी अवधि के समान है, लेकिन यात्रियों की मृत्यु/गंभीर चोटों से जुड़ी गंभीर दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है।

रेलवे सुरक्षा आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में 31.10.2023 तक पांच गंभीर दुर्घटना मामलों की जांच की जा रही है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि में दो दुर्घटना मामलों की जांच की जा रही है।

सीसीआरएस के मुताबिक, इन पांच मामलों में से तीन मामले टक्कर के, एक पटरी से उतरने का और एक आग लगने का है। सीसीआरएस ने कहा कि इस साल हुई टक्कर के तीन मामलों में से दो मामले लोको पायलट (एलपी) द्वारा सिग्नल को खतरे में डालने (एसपीएडी) के कारण और एक सिग्नलिंग स्टाफ की गलती के कारण हुआ है।

स्टेशन यार्ड में गैर-पृथक लाइनों पर एक साथ ट्रेन की आवाजाही की अनुमति देने के लिए जोनल रेलवे को दिए गए लचीलेपन पर सवाल उठाते हुए, सीसीआरएस ने कहा, "इस परिदृश्य में एसपीएडी के कारण टकराव की संभावना बढ़ने की संभावना है। रेलवे सुरक्षा आयोग का विचार है कि इन संशोधनों को वापस लिया जाना चाहिए।

संशोधित मानदंड का उपयोग

सीसीआरएस ने परिचालन सुरक्षा से संबंधित कई अन्य मुद्दों को भी उठाया है जैसे गैन्ट्री सिग्नल का प्रावधान करना, सावधानी सिग्नल पर गति प्रतिबंध तय करना, पूरे वर्ष सभी ट्रेनों में कोहरे सुरक्षा उपकरण रखना और लोको-पायलटों की नियमित परामर्श देना।

हालांकि, रेलवे बोर्ड द्वारा जोनों को प्रसारित लिखित संचार से पता चलता है कि केवल स्टेशन यार्डों में गैर-पृथक लाइनों पर ट्रेनों की एक साथ आवाजाही के संबंध में विचार मांगे गए हैं।

सीसीआरएस की चिंता का हवाला देते हुए, रेल मंत्रालय ने इस साल 26 फरवरी को सभी रेलवे जोनों से अपने अनुभव और राय के साथ उन मामलों की संख्या का विवरण प्रदान करने को कहा, जिनमें संशोधित मानदंड का उपयोग किया गया है।

19 मार्च को मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे (दक्षिणी रेलवे को छोड़कर) को रिमाइंडर भेजा।

HDFC बैंक का नया रिकॉर्ड; चोथी तिमाही में दिया 25 लाख करोड़ रुपये का लोन

एचडीएफसी बैंक ने रैगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि 2024 को समाप्त चौथी तिमाही में उसकी लोन बुक 25 लाख करोड़ रुपये को पार कर गयी। 31 मार्च 2024 तक बैंक की सकल अग्रिम राशि 25.08 लाख करोड़ रुपये थी जो 31 मार्च 2023 तक 16.14 लाख करोड़ रुपये से 55.4 प्रतिशत अधिक थी।

एचडीएफसी बैंक ने गुरुवार को कहा कि मार्च 2024 को समाप्त चौथी तिमाही में उसकी लोन बुक 25 लाख करोड़ रुपये को पार कर गयी। बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में बताया कि 31 मार्च, 2024 तक बैंक की सकल अग्रिम राशि 25.08 लाख करोड़ रुपये थी, जो 31 मार्च, 2023 तक 16.14 लाख करोड़ रुपये से 55.4 प्रतिशत अधिक थी।

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के आंकड़ों में पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड का परिचालन शामिल है, जिसका 1 जुलाई, 2023 को एचडीएफसी बैंक के साथ विलय हो गया था। इसलिए पिछले वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

हालांकि, तिमाही-दर-तिमाही आधार पर लोन वृद्धि 31 दिसंबर, 2023 के अंत में 24.69 लाख करोड़ रुपये की तुलना में मामूली 1.6 प्रतिशत बढ़ी। यह वृद्धि तुलनीय है।

ग्रामीण बैंकिंग ऋण में बढ़ोतरी

बैंक के आंतरिक व्यापार वर्गीकरण के अनुसार, घरेलू खुदरा ऋण (Domestic Retail Loan) 31 मार्च, 2023 के दौरान लगभग 109 प्रतिशत और 31 दिसंबर, 2023 के दौरान लगभग 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

बैंक के वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकिंग ऋण में 31 मार्च, 2023 के दौरान 24.6 प्रतिशत और 31 दिसंबर, 2023 के दौरान लगभग 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3 लाख करोड़ हो गया कंपनी का एम-कैप, एक दिन पहले ही देश के टॉप-10 अमीरों में शामिल हुए थे दमानी

फोर्ब्स ने अरबपतियों की लिस्ट (Forbes Worlds Billionaires List 2024) जारी कर दी है। इस लिस्ट में भारत के करीब 200 अरबपति शामिल है। इन नामों में D-Mart के संस्थापक राधाकिशन दमानी भी शामिल है। वह भारत के अरबपतियों की लिस्ट में नौंवे स्थान पर हैं। आज डी-मार्ट के शेयर (D-Mart share Price) में तेजी आई है जिसके बाद कंपनी का मूल्यांकन 3 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

आज सुबह से शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में डी-मार्ट के शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। शेयर में आई तेजी के बाद डी-मार्ट का एम-कैप (D-Mart Mcap) 3 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। हालांकि, कंपनी ने पहले भी यह मुकाम हासिल किया था।

आज कंपनी का स्टॉक 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। डीमार्ट के मालिक द्वारा मार्च तिमाही में परिचालन से अपने स्टैंडअलोन राजस्व में 20 फीसदी की वृद्धि आई है। इस वृद्धि के बाद कंपनी का रेवेन्यू 2,393.46 करोड़ रुपये पहुंच गया है। कंपनी के रेवेन्यू में आई तेजी ने शेयर को बढ़त हासिल करने में मदद की है।

आज सुबह बीएसई पर कंपनी का शेयर (D-Mart Share) 3.73 प्रतिशत चढ़कर 4,626 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई पर डी-मार्ट के शेयर 3.66 फीसदी बढ़कर 4,623.95 रुपये प्रति पीस पर पहुंच गया।

कंपनी के शेयर एनएसई और बीएसई पर लगभग 6 प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 4,715 रुपये और 4,710.15 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। पिछले तीन लगातार सत्रों में स्टॉक में 12 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

बीएसई पर इंट्रा-डे कारोबार के दौरान कंपनी का बाजार मूल्यांकन 10,824.95 करोड़ रुपये बढ़कर 3,01,029.12 करोड़ रुपये हो गया। अक्टूबर 2021 में डी मार्ट का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) 3 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया।

आज वाला बीएसई सेंसेक्स 95.08 अंक या 0.13 प्रतिशत गिरकर 73,781.74 पर और एनएसई निफ्टी 17.95 अंक गिरकर 22,416.70 पर आ गया।

शेयरों में क्यों आई तेजी

एवेन्यू सुपरमार्ट्स डी-मार्ट ने बुधवार को कहा कि उसने मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में परिचालन से अपना स्टैंडअलोन राजस्व 12,393.46 करोड़ रुपये बताया है। यह एक साल पहले की समान अवधि में 10,337.12 करोड़ रुपये से 19.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

कंपनी का राजस्व मार्च 2022 को समाप्त तिमाही में दर्ज 8,606.09 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021 की पिछली तिमाही में 7,303.13 करोड़ रुपये से अधिक है। 31 मार्च 2024 तक, डीमार्ट स्टोर्स की कुल संख्या 365 थी।

दादा के खरीदे शेयर पर क्या पोते का होता है अधिकार, यहां जानें क्या कहता है नियम

दादा की प्रॉपर्टी पर बेटे का तो अधिकार होता ही पर उसके साथ ही पोते का भी अधिकार होता है। लेकिन कई बार सवाल आता है कि क्या दादा के खरीदे शेयर पर पोते का अधिकार होता है। शेयर बाजार में इसको लेकर क्या नियम है। अगर आपके दादा जी ने शेयर खरीदा है तो उसे ट्रांसफर करने का प्रोसेस क्या है?

नई दिल्ली। पिता की संपत्ति पर या दादा की संपत्ति पर किसका हक होता है, इसे लेकर तो आपने कई बार चर्चा सुनी होगी, खबरों में भी पढ़ा होगा। लेकिन शेयरों को लेकर ऐसी कोई व्यवस्था होती है, इस बारे में क्या आप जानते हैं? क्या संपत्ति की तरह ही शेयरों पर भी ऐसे नियम लागू होते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं।

हाल ही में चंडीगढ़ के डॉक्टर ने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि उनके दादा ने 30 साल पहले 500 रुपये का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का शेयर खरीदा था, जिसकी वर्तमान में कीमत 3.75 लाख रुपये है।

इस तरह के मामले कई बार देखने को मिलते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या दादा के शेयर पर पोते का अधिकार है। इसके अलावा शेयरहोल्डर के शेयर पर कानूनी अधिकार किसका होता है और इस शेयर को कैसे ट्रांसफर किया जाता है।

अगर आपके भी दादा-दादी ने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो वह इस शेयर को आसानी से ट्रांसफर करवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट (Demat Account) के जरिये आसानी से स्टॉक ट्रांसफर हो सकते हैं।

डीमैट अकाउंट एक तरह का बैक अकाउंट ही है। बस इन दोनों अकाउंट में यह फर्क है कि बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होते हैं वहीं डीमैट अकाउंट में शेयर-सिक्योरिटीज का लेनदेन होता है।

भारत में डीमैट अकाउंट की शुरुआत 1995-69 में हुई थी। उस वक्त शेयर फिजिकल फॉर्म में उपलब्ध होते थे। सिंग्ल या ज्वाइंट तरीके से डीमैट अकाउंट ओपन किया जा सकता है।

क्या शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं?

जिस व्यक्ति ने शेयर खरीदा अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तब सिक्योरिटीज यानी शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए कानूनी वारिसों को जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) से संपर्क करना होगा।

अगर शेयर फिजिकल फॉर्म में है तब उस कंपनी से संपर्क करना होगा जिसके शेयर्स हैं। यदि शेयरहोल्डर ने नॉमिनी का नाम दिया है तब शेयर ट्रांसफर करने का प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा। शेयर ट्रांसफर के लिए नॉमिनी को ट्रांसमिशन फॉर्म और डेथ सर्टिफिकेट की एक नोटराइज्ड कॉपी सबमिट करनी होगी। यह कॉपी गजटेड ऑफिसर या नोटरी पब्लिक से अटेस्ट होना चाहिए।

डीपी के ऑफिस या फिर वेबसाइट से नॉमिनी को ट्रांसमिशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म भरकर और डॉक्यूमेंट अटैच करके इसे जमा करना है, फॉर्म को वेरिफाई किया जाएगा। अगर फॉर्म सही होता है तो नॉमिनी के डीमैट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

सीएनआई रिसर्च लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किशोर ओस्तवाल के अनुसार

इसके आगे वह कहते हैं कि मृत्यु के बाद पोते को शेयर हस्तांतरित करने की एकमात्र संभावना उचित वसीयत है। वैकल्पिक रूप से वह जीवित रहने पर इन शेयरों को सीधे अपने पोते को उपहार में दे सकता है और शेयरों को बाजार से पोते के खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है। पोते को शेयरों के हस्तांतरण के लिए सेबी अधिनियम के स्टॉक एक्सचेंज में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

मार्च में महंगी हो गई वेज थाली, नॉन-वेज थाली के दाम में गिरावट; क्या है वजह

क्रिसिल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले मार्च में वेज थाली की कीमतों में तेजी और मांसाहारी थाली की कीमतों में गिरावट आई है। प्याज टमाटर और आलू की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से वेज थाली महंगी हुई। वहीं पोल्ट्री की कीमतों में गिरावट के कारण मांसाहारी थाली में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है। यहां पढ़ें पूरी खबर..

नई दिल्ली। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस अपनी मासिक ₹रोटी चावल दर₹ रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च महीने में वेज थाली की कीमतों में 7 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है। दरअसल, प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों में बढ़ोतरी ने इनकी कीमतों में इजाफा किया है।

वहीं, अगर नॉन-वेज थाली की बात करें तो पोल्ट्री की कीमतों में गिरावट के कारण मांसाहारी थाली में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है।

रोटी, सब्जियां, चावल, दाल, दही और सलाद वाली सब्जी थाली की कीमत मार्च में बढ़कर 27.3 रुपये प्रति प्लेट हो गई, जो एक साल पहले की अवधि में 25.5 रुपये थी, लेकिन सस्ती थी। वहीं, फरवरी 2024 में वेज थाली की कीमत 27.4 रुपये से अधिक थी।

क्यों महंगी हुई वेज थाली

देश में प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों में सालाना आधार पर वृद्धि देखने को मिली है। इस तेजी की वजह से वेज थाली के दाम बढ़ गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में सालाना आधार पर प्याज 40 प्रतिशत, टमाटर 36 प्रतिशत और आलू 22 फीसदी महंगा हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार कम आवक के कारण एक साल पहले की तुलना में चावल की कीमतें 14 प्रतिशत और दालों की कीमतें 22 प्रतिशत बढ़ गईं।

नॉन-वेज थाली के मामले में जिसमें केवल दाल को चिकन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एक साल पहले की अवधि में 59.2 रुपये के मुकाबले नॉन-वेज थाली के दाम घटकर 54.9 रुपये हो गई, लेकिन फरवरी से पहले 54 रुपये प्रति थाली की तुलना में अधिक थी।

ब्रॉयलर की कीमतों में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है। साल-दर-साल आधार पर मांसाहारी थाली की लागत में गिरावट का प्राथमिक कारण यही था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी से तुलना करने पर रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत और अधिक मांग के कारण ब्रॉयलर की कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भाजपा के भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल की नामांकन सभा में उमड़े हजारों कार्यकर्ता

कांग्रेस झूठ और लूट की दुकान, भाजपा जो कहती है वह करती है : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा के भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल की नामांकन सभा में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ और लूट में विश्वास करती है जबकि भाजपा जो कहती है वह करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातिवाद और तुष्टीकरण के नाम पर काम करती है। 2014 से पहले देश में कांग्रेस का राज था तब देश आतंक और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था आए दिन इतने लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे जिनके जीरो पढ़े भी नहीं जा सकते थे यहां तक की जमीन पर घोटाले आसमान में घोटाले और तो और पाताल में भी घोटाले हुए देश में भाई और आतंक का माहौल था यहां तक की आतंकवादी देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के सिर काट कर ले जाते थे और सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रहती थी। उस वक्त की गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार ने कभी गरीब से नाता जोड़ने का काम नही किया। गरीब और किसान की चिंता यदि किसी ने की है तो वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। महिलाओं के दर्द को समझने का काम भी मोदी सरकार ने किया है, घर घर शौचालय बनाकर महिलाओं को सम्मान दिया है। गरीब का बैंक खाता खुलवाने के साथ ही किसानों को लाभ पहुंचाने का काम भी मोदी ने किया है। धारा 370 हटाने की बात हो या राम मंदिर निर्माण की, मोदी को कहते हैं वह करके बताते हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने भगवान श्री राम का निमंत्रण ठुकरा दिया उन कांग्रेसियों में से राम भी निकल गए हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद 90 दिन में अपने संकल्प पत्र के 45 फीसदी वादों को पूरा किया है। यह जनता की सरकार है जो जनता के बीच जाती है, जनता की सुनती है और जनता के काम करती है। प्रदेश में युवाओं के सपनो को तोड़ने का काम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किया और पेपर लीक घोटाले चरम पर पहुंचे। भाजपा सरकार के गठन के साथ ही ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का काम प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने किया। 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराकर प्रदेश की 73 लाख बहिनों को लाभ पहुंचाया गया, किसानों की सम्मान निधि को 2000 रुपए बढ़ाकर 8000 रुपए किया गया। गेंहू का समर्थन मूल्य 2275 से बढ़ाकर 2400 रुपए किया। आंगनबाड़ी केंद्र की सहयोगिनियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों के मानदेय में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपए करने का काम भी भाजपा सरकार ने किया।

उन्होंने भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र को लेकर कांग्रेस द्वारा की गई घोषणाओं को भी आड़े हाथों लेते हुए जनता से पूछा कि वे सब पूरी हुई या नहीं तो जनता ने एक स्वर में उन घोषणाओं को थोथी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसका जवाब भी जनता ही देगी। इस बार भीलवाड़ा में भाजपा की जीत का इतिहास जनता के विश्वास और समर्थन से बनेगा।

नामांकन सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश सहप्रभारी विजया ताई रहाटकर ने दशा माता के त्योंहार के बावजूद महिलाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति को लेकर कहा कि यह वह भूमि है जहां परंपराओं और सनातन संस्कृति को संभालते हुए राष्ट्र के विकास की भी बात की जाती है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश का वातावरण मोदीमय हो गया है। आज भाजपा की पूंजी ही यही है कि पार्टी ने देश की जनता, हर वर्ग हर समाज के लिए काम किया है। जबकि कांग्रेस की पूंजी पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, किसानों के हितों से कुठाराघात है। प्रदेश में भजनलाल शर्मा सरकार ने राजस्थान की तस्वीर को बदलने का काम किया है। लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देकर पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया है। पार्टी के तीन प्रमुख मुद्दे सांस्कृतिक उन्नयन, दलित कल्याण एवं विकसित भारत का संकल्प है, उसी प्रकार विकसित भीलवाड़ा के मुद्दे को आधार बनाकर एकजुट और एकमुखी होकर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं भीलवाड़ा में शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र में विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के प्रयास भी प्राथमिकता रहेगी।

जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि सभा में आशीर्वचन प्रदान करते हुए महामंडलेश्वर हंसाराम जी ने उपस्थित जन मेदिनी को स्वयं के साथ रिश्तेदारों, इष्ट मित्रों को मतदान के लिए जागरूक करने का संकल्प दिलाया। नामांकन सभा में महंत रामदास जी रामायणी, परमेश्वरदास जी पंचमुखी दरबार, शांतिदास जी महाराज, गोविंद साई हरिसेवा ने भी मंच से आशीर्वाद प्रदान किया। इससे पूर्व प्रारंभ में जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने भीलवाड़ा की धरा पर जिला संगठन की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित समस्त अतिथियों का स्वागत करते हुए भीलवाड़ा सीट पर भाजपा की प्रचंड जीत का विश्वास जताया।

इस अवसर पर लोकसभा सह प्रभारी गजपाल सिंह राठौड़, जिला संगठन प्रभारी रतनलाल गाडरी, लोकसभा समन्वयक अतरसिंह भडाना, सांसद सुभाष बहेड़िया, पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, जिला प्रमुख बरजीदेवी भील, विधायक उदयलाल भडाणा, गोपाल खंडेलवाल, लालाराम बैरवा, गोपीचंद मीणा, लादूलाल पीतलिया, जब्बरसिंह सांखला, विधायक प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी, लोकसभा संयोजक शक्तिसिंह कालियास, बूंदी जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर, बालुलाल चौधरी, नामांकन सभा प्रभारी सभापति राकेश पाठक सहित कई वरिष्ठ नेता मंचासीन रहे। नामांकन सभा का संचालन जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद त्रिपाठी एवं जिला महामंत्री वेदप्रकाश खटीक ने किया। अंत में आभार विधायक अशोक कोठारी ने व्यक्त किया। इस अवसर पर भीलवाड़ा लोकसभा की आठों विधानसभाओं से आए लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति एवं कोर कमेटी सदस्य, विधानसभा चुनाव संचालन समिति सदस्य, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा समन्वयक, विधानसभा संयोजक, जिला पदाधिकारी, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान, उपप्रधान, मोर्चा अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पार्षद गण सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भि के पाडीयान कि सुरख्र लेकर तिन RTI कर्मी के नाम पर मामला

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वरः नवीन ओडिशा और 5 टी चेयरमैन कार्तिक पांडियन की सुरक्षा से जुड़ी गलत जानकारी देने के आरोप को कमिश्नरेट पुलिस ने गंभीरता से लिया है। ओडिशा सूचना अधिकार अभियान (ओएसए) ने कहा कि पांडियन की सुरक्षा के लिए 74 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत कमिश्नरेट पुलिस के रिजर्व पुलिस कार्यालय से एक पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है ।हालांकि, कमिश्नरेट पुलिस ने इसे फर्जी पत्र होने का आरोप लगाया है। इस संबंध में आरक्षी निरीक्षक भगवान पानीग्राही ने शहीदनगर थाने को सूचना दी है । उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 419, 420, 465, 468, 469, 471, 505, 34 और 66डी आईटी एक्ट के तहत मामला (नंबर 193/2024) दर्ज कर लिया है और जांच जारी रखी है । इस मामले में पुलिस ने तीन आरटीआई कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया है । ये हैं प्रदीप प्रधान, प्रकाश चंद्र दास और श्रीकांत पाकल। हालांकि, शहीद नगर के पुलिस अधिकारी अशोक नायक ने बताया कि इस मामले में और जांच की जा रही है ।

पिछले 29 मार्च को ओएसए ने पत्र वाली जानकारी के बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी । ओएसए ने पांडियन की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस कर्मियों को वापस लेने की मांग की, जो राज्य के खजाने से खर्च किया गया था। इसके बाद बीजेपी ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी की । हालाँकि, ओएसए ने दावा किया कि यह जानकारी आरटीआई अधिनियम के तहत रिजर्व पुलिस कार्यालय से प्राप्त की गई थी, जबकि कमिश्नरेट पुलिस ने इसे झूठा पत्र कहकर खारिज कर दिया और अब यह एक अलग मुद्दा बन गया है।

निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी ने दिया भाजपा को समर्थन, वरिष्ठ नेताओं की पार्टी में हुई वापसी

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल की नामांकन सभा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में भाजपा को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी का मंच पर प्रदेश सहप्रभारी विजयाताई रहाटकर ने शाल ओढ़ाकर स्वागत किया। साथ ही पूर्व जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, पूर्व न्यास अध्यक्ष एल एन डाड, उपसभापति रामनाथ योगी, पूर्व नगर अध्यक्ष कन्हैयालाल स्वर्णकार की भी भाजपा में वापसी के अवसर पर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इसी के साथ पूर्व सभापति ललिता समदानी, निर्दलीय पार्षदों में वार्ड 62 से ओम पाराशर साईंराम, वार्ड 41 से आशा शर्मा, वार्ड 48 से सागर पांडे, वार्ड 35 से कैलाश मूंदड़ा, वार्ड 59 से बदाम देवी माली, वार्ड 20 से राजेंद्र पोरवाल, वार्ड 36 से सुशीला जैन एवं वार्ड 37 से कांग्रेस पार्षद मोहिनी माली, वार्ड 10 से कांग्रेस पार्षद महेंद्र घबरानी ने भी आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र से शकरगढ़ पूर्व सरपंच किशोर शर्मा, जहाजपुर के पूर्व प्रधान तुलसी भाटी, पंचायत समिति सदस्य मोहित मीणा, ऊंचा पूर्व सरपंच राजेश जैन, ठीठोड़ा जागीर पूर्व सरपंच रामगोपाल शर्मा, पूर्व पार्षद कैलाश रेगर सहित कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया।

मेरठ से' राम को हराने' पर तुले हैं अखिलेश,तीसरी बार बदला कैंडीडेट

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कथित इंडिया गठबंधन टीम के मजबूत विकेट कीपर अखिलेश यादव मेरठ लोकसभा सीट से प्रभु श्रीराम को किसी भी सूरत में हराने पर तुले हुए है। लेकिन प्रभु श्रीराम (अरूण गोविल) को हराने की उनकी हर चाल उल्टी पडती दिखाई दे रही है।

इसी कन्फ्यूजन में अखिलेश यादव ने तीसरी बार कैंडीडेट को बदल दिया है। राम (अरूण गोविल) के खिलाफ अब तक सपा द्वारा घोषित उम्मीदवारों में सबसे पहले भानू प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। भानू प्रताप सिंह जब तक नॉमिनेशन भरने की तैयारी में कमर कसते, जब तक उनकी जगह अतुल प्रसाद का नाम घोषित कर दिया गया। अखिलेश यादव के कन्फ्यूजन का अंत यहीं नहीं हुआ। हद तब हो गई जब दोनों मेल चेहरों को दरकिनार कर तीसरी बार एक महिला कैंडीडेट पूर्व विधायक की पत्नि और पूर्व मेयर सुनीता वर्मा का बतौर कैंडीडेट के' राम' अरूण गोविल के खिलाफ नाम घोषित कर मैदान में उतार दिया है। लेकिन सच यह भी है कि इस वीरांगना सुनीता वर्मा के हाथ से भी कभी भी तलवार खींचीं जा सकने की दुविधा का खौफ है। क्योकि कन्फ्यूजन की हालात में किसी चौथे उम्मीदवार को भी अखिलेश द्वारा सेहरा पहनाया जा सकता है।

भाजपा प्रदेश सहप्रभारी विजया रहाटकर ने विधायकों, पूर्व विधायकों की विशेष बैठक ली

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश सहप्रभारी विजया रहाटकर ने लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल की नामांकन सभा के बाद भाजपा जिला कार्यालय पर भाजपा विधायकों एवं पूर्व विधायकों की एक विशेष बैठक ली जिसमें उन्होंने 5 अप्रैल को बूथ स्तर पर टिफिन बैठकों के आयोजन, 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर विचार विमर्श किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर आठों विधानसभाओं में पार्टी की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी जगह भाजपा की भारी बहुमत से जीत के लिए सशक्त रणनीति बनाकर काम करने का आह्वान किया।

जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि बैठक में लोकसभा सहप्रभारी गजपाल सिंह राठौड़, लोकसभा समन्वयक अतरसिंह भडाना, जिला संगठन प्रभारी रतनलाल गाडरी, लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, जिला प्रमुख बरजीदेवी भील, लोकसभा संयोजक शक्तिसिंह कालियास, विधायक उदयलाल भडाना, गोपीचंद मीणा, गोपाल खंडेलवाल, लादूलाल पीतलिया, लालाराम बैरवा, जब्बरसिंह सांखला, अशोक कोठारी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, कालूलाल गुर्जर, पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर, बालूराम चौधरी, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवांगी कानावत, जिला महामंत्री वेदप्रकाश खटीक, भगवती प्रसाद जोशी उपस्थित थे।

डॉ राजीव मिश्रा समेत डॉ महेश शर्मा और महेंद्र नागर एवं अन्य प्रत्याशी उतरे गौतमबुद्ध नगर लोकसभा मैदान में

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। आगामी 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए गौतमबुद्धनगर लोकसभा सीट से आज तक 30 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। अब तक तीन प्रमुख प्रत्याशियों सहित कुल 27 लोगों ने पर्चे दाखिल किए हैं जबकि आज 14 और लोगों ने नामांकन पत्र लिए हैं। आज गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन था।

जे एन पी प्रत्याशी और यहाँ की जनता के लिये समर्पित डॉ राजीव मिश्रा ने पूजा अर्चना के बाद जिलाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया। नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथपत्र में उन्होंने अपनी चल अचल संपत्तियों, ऋणों व अपने ऋणी लोगों का भी ब्यौरा पेश किया है। डॉ. राजीव मिश्रा को जयहिंद नेशनल पार्टी का चुनाव चिन्ह बाँसुरी है जिसके समर्थन में आज काफी संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक नामांकन के समय उनके साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद थे ।

उनके अलावा दस और लोगों ने भी नामांकन किया। इनमें दो नाम उल्लेखनीय हैं। नोएडा में फ्लैट बालों की आवाज उठाते रहे एक्टिविस्ट एड.नवीन दुबे ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया।

एक स्वयंभू फायर ब्रांड के तौर पर काम करने वाले एडवोकेट नवीन दुबे का नोएडा की आवासीय सोसायटियों में अच्छा प्रभाव बताया जाता है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरने वाली रितु सिन्हा की पहचान नोएडा क्षेत्र की झुग्गी-बस्तियों में सामाजिक कार्य करने वाली एक सक्रिय महिला की है।

आज नामांकन का आखिरी दिन था। तत्पश्चात 8 अप्रैल तक नाम वापसी की सुविधा रहेगी। 8 अप्रैल को नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों के बीच 9 अप्रैल से विधिवत चुनावी जंग शुरू हो जाएगी। चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और अधिकाधिक मतदान से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं।

मुस्लिमों के संदर्भ में बदली है भाजपा की रणनीति...

भूल सुधार : कल दिनांक 4 अप्रैल के अंक में यह खबर भूलवश गलत प्रकाशित हो गई थी। जिसमें लिए प्रकाशन को खेद है।

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के संदर्भ में अपनी रणनीति पर परिस्थित के तहत रद्दोबदल करने की छिडी कवायद पर अमल करना चाह रही है। पार्टी के दो धुरंधरों मोदी-शाह युग में 'वोट की गारंटी दो, टिकट' लो की रणनीति से मुसलमानों के प्रति भाजपा के दृष्टिकोण में बडा बदलाव देखने को मिल सकता है।

भाजपा में बदले दृष्टिकोण के संकेत साफ है।मुसलमानों में पैठ बनाने के लिए पार्टी दशकों से जी तोड कोशिशों में जुटी हुई है। बशर्ते इस वर्ग को उन मुश्किल सीटों पर अपनी प्रांसांगिकता साबित करनी होगी,जहां उनके वोट निर्णायक स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रभाव वाले राज्यों में मुसलमानों पर दांव लगाने से परहेज बरतने का स्पष्ट संकेत दिया है।उल्लेखनीय है कि भाजपा अब तक 405 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। केरल की मल्लपुरम सीट एकमात्र ऐसी सीट है जहां से पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम को उतारा है।

बता दें कि कभी पार्टी का मुस्लिम चेहरा रहे शाहनवाज हुसैन ,मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेताओ को उम्मीदवारों की सूची में जगह नहीं मिली है। वह भी तब,जब देश की 65 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओ की भागीदारी 30 से 65 फीसदी ,तो करीब 35 सीटों पर प्रभावशाली उपस्थिति है। भाजपा रणनीति में बडा बदलाव आया है।पार्टी अब वोट की कीमत पर ही इस समुदाय को टिकट देना चाहती है। उल्लेखनीय है कि दो साल पहले जब हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम नरेंद्र मोदी ने पसमांदा मुसलमानों तक पहुंच बनाने का आह्वान किया,तब एक बारगी लगा कि इस बार पार्टी प्रभाव वाले राज्यों में इस वर्ग को मौका देगी।

आंकडों पर सरसरी नजर डालें तो, 100 सीटों पर मुस्लिमों का व्यापक असर 65 सीटों पर 30 से 65 फीसदी मुस्लिम आबादी 14 सीटें यूपी की तो 13 सीटें पश्चिम बंगाल की ,8 केरल,7 असम,5 जम्मू-कश्मीर, 4 बिहार,,3- मध्य-प्रदेश, दिल्ली,गोवा,हरियाणा,महाराष्ट्र, तेलंगाना,की 2-2 और तमिलनाडू की एक सीट है। हालांकि भाजपा,अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने अपने तंई अब तक कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं।अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने इस आह्वान के बाद इस वर्ग में पहुंच के लिए बिहार,उत्तर प्रदेश, में भाईचारा,सूफी सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इस दौरान करीब '18 लाख मोदी मित्र 'बनाए गए। तब उम्मीदवारी में मुसलमानों को मौका मिलने की धारणा को मजबूती मिली थी। बता दें की भाजपा की स्थापना के बाद 1980 में भी मुस्लिमों में पैठ बनाने की कोशिश की।इस वर्ग के नेताओ को बार-बार राज्यसभा और सत्ता मिलने पर सरकार में मौका दिया गया।बावजूद इसके पार्टी इस वर्ग में अपनी पैठ मजबूत करने में नाकाम रही। 2014 में भाजपा के सत्तासीन होने के बाद भाजपा ने मंत्रिमंडल में दो मुस्लिम नेताओ एमजे अकबर,नजमा हेपतुल्ला को जगह दी।हालांकि पार्टी के 7 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतने में असफल रहे थे। 1977 और 1989 में आरिफ बेग चुनाव जीते। उन्हें कई बार मंत्री भी बनाया। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी बस एक बार ही चुनाव जीते,सैयद शाहनवाज हुसैन इकलौता मुस्लिम चेहरा है,जिन्होने 3 बार लोकसभा चुनाव में जीत हांसिल की है। इसी कडी में सिकंदर बख्त ने भाजपा मंत्रिमंडल से लेकर संगठन में भी उच्च पद संभाला बहरहाल भाजपा ने मोदी युग में रणनीति से लेकर और कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं।जिसका असर पड़ शुरू हो चुका है।

राजस्थान से चामुण्डा माताजी मंदिर के मुख्य पुजारी चन्द्राराम का हैदराबाद में भव्य स्वागत

हैदराबाद डी पोचमपल्ली। राजस्थान से चामुण्डा माताजी मंदिर के मुख्य पुजारी (भोपाजी) एवं चामुण्डा माताजी मंदिर के कोटवाल चुन्नीलाल का आई मां ट्रेडर्स मुख्य प्रबंधक जगदीश सोलंकी , गोविंद राम हाम्बड़ , तेजाराम हाम्बड़ , सोलंकी सचिन, राहुल हाम्बड़ द्वारा भव्य स्वागत किया सीरवी समाज शमशाबाद बडेर सचिव भोलाराम पांवर, शिक्षा समिति अध्यक्ष केसाराम, राजुराम, भंवरलाल डी पोचमपल्ली का स्वगत किया है चामुण्डा माताजी मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा जो भगवान के ऊपर के ऊपर विश्वास रखना और भक्त सही मार्ग चलेगा उसके ऊपर सदैव माता जी का आशीर्वाद बना रहेगा । शमसाबाद बडेर के सचिव भोलाराम पांवर जो व्यक्ति की भावना अच्छी रहेगी माताजी के ऊपर आस्था रखना एवं विश्वास रखना है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023